वर्ष 01 | अंक 03 | अप्रैल 2024 | मूल्य 100/-

प्रयास करेंट अफेयर्स

UPSC | BPSC एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु मासिक पत्रिका

मुख्य आकर्षण

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट | नई इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति 2024 | पीएम-सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना | भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 | डीआरडीओ का 'मिशन दिव्यास्त्र' बिहार स्पेशल करेंट अफेयर्स

दैनिक अपडेट्स के लिए जुड़ें : Prayas IAS Academy

प्रयास
IAS ACADEMY
An Institute for UPSC & BPSC

ADMISSION OPEN
upto 50% OFF*

ATTENTION
UPSC / BPSC Aspirants

Boost your AIR with

GS TARGET COURSE

FOR BPSC & UPSC

हिंदी माध्यम | ENGLISH MEDIUM

MODE: Offline & Online

JOIN THE TEAM OF "Experienced & Renowned Faculties at PRAYAS IAS ACADEMY"

Mr. M K Sahay
Academic Director, PRAYAS IAS
Ex. Sr. Faculty (History) RAU'S IAS, Delhi
27 years & above Experience

Mr. Neeraj Nachiketa
Ex. Sr. Faculty (Sc. Tech)Vajiram & Ravi, Delhi
25 years & above Experience

Mr. DK Upadhyay
GEOGRAPHY

Mr. Satyam Kumar
CSAT & DI

Mr. Prabhat Kumar
ESSAY

Mr. Kiran Anishetti
POLITY, IR & GOVERNANCE

Mr. Nitin Kumar
POLITY, IR & GOVERNANCE

Md. Parvej
POLITY, IR & GOVERNANCE

Mr Amit Mathur
ECONOMY

Md. Rizwan Alam
ETHICS

Mr. Abhishek Tiwari
CURRENT AFFAIR

प्रयास करेंट अफेयर्स

वर्ष 01 | अंक 03 | अप्रैल 2024 | मूल्य - 100/-

प्रधान संपादक : राहुल राज

संपादकीय सलाहकार : एस. के. सिंह, एम. के सहाय, डी.के. उपाध्याय

कार्यकारी संपादक : राजेश प्रियदर्शी

संपादन सहयोग : टीम प्रयास IAS

लेआउट एवं डिजाइन : निशांत कुमार झा

प्रयास IAS ACADEMY

कार्यालय

**Pushpanjali Palace,
Boring Road Chauraha,
Patna-800001**

8818810183 | 8818810184

www.prayasiasacademy.com

prayasiasacademy101@gmail.com

prayasiasacademy

© **कॉपीराइट : PRAYAS IAS ACADEMY**

इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रकाशन अथवा उपयोग, प्रतिलिपिकरण, ऐसे यंत्र में भंडारण जिससे इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता हो या स्थानांतरण, किसी भी रूप में या किसी भी विधि से (इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या किसी अन्य प्रकार से) प्रकाशक की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकता। यद्यपि इस पत्रिका के प्रकाशन से पूर्व सम्पादक ने हर प्रकार की सावधानी बरती है। फिर भी किसी प्रविष्टि/तथ्य सम्बंधित किसी प्रकार के वाद पर सम्पादक मंडल जिम्मेदार नहीं होगा। सभी विवादों का निपटारा पटना (बिहार) न्यायिक क्षेत्र में होगा।

Editor's Desk

प्रिय पाठकों,

"सपने बड़े हों, तो छोटी जगह से आना कोई मायने नहीं रखता"

उपर्युक्त कथन डॉ. एपीजे अब्दुल कलम की है। वे बहुत छोटी जगह से आने के बावजूद, खुद को किसी भी तरह से छोटा महसूस नहीं किया, क्योंकि उनके सपने बड़े थे। वे कहते हैं कि उन्हें अपने पूरे छात्र जीवन में जिस बात ने पढ़ाई जारी रखने के लिए लगातार प्रेरित किया, वह था कुछ बड़ा हासिल करने का जज्बा, एक बेहतर जीवन जोने की चाह और अनुशासित जीवनशैली के लिए प्रतिबद्धता।

वाकई में, अनुशासन से रहना, जिंदगी में लक्ष्य तय करने और उस तक पहुंचने के बीच एक पुल की तरह काम करता है। अनुभवों के आधार पर उनहोंने बताया कि चार पक्के तरीके हैं, जिनसे आपको सफलता पाने में मदद मिल सकती है। पहले, बीस वर्ष की उम्र तक अपने जीवन लक्ष्य तय कर लेना। दूसरे, अहम किताबों, गुरुजनों और महान हस्तियों से ज्ञान हासिल करने का जुनून होना। तीसरे, कड़ी मेहनत और अनुशासित जीवनशैली का पालन करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना। और चौथे, अपने चुने हुए रास्ते पर पक्के इरादे के साथ बिना ठहरे चलते रहना।

आपके सपने को पूरा करने और उच्च लक्ष्य की प्राप्ति करने की दिशा में PRAYAS IAS ACADEMY सर्वोत्तम मार्गदर्शन प्रदान करता है, जहाँ देश के अनुभवी शिक्षकों, विषय-विशेषज्ञों एवं मेंटर्स द्वारा सिविल सर्विसेज की तैयारी करायी जाती है। यहाँ प्रतिदिन करेंट अफेयर्स, सामान्य अध्ययन, न्यूज पेपर रिडिंग, राइटिंग स्किल्स, पर्सनालिटी डवलपमेंट एवं टेस्ट सीरीज से संबंधित कक्षा का संचालन किया जाता है। साथ ही सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को मजबूती प्रदान करने के लिये इस संस्थान द्वारा "प्रयास करेंट अफेयर्स" मासिक पत्रिका का भी प्रकाशन किया जा रहा है। पिछले दो अंकों की अपार सफलता के पश्चात् इस पत्रिका का तीसरे अंक आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत गर्व हो रहा है। आपको बता दें कि इस पत्रिका में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रम एवं बिहार स्पेशल करेंट अफेयर्स का संकलन किया गया है, जो वर्तमान प्रतियोगी परीक्षा पैटर्न के अनुरूप है।

प्रयास करेंट अफेयर्स पत्रिका आपको सर्वोत्तम मार्गदर्शन और पाठ्य-सामग्री प्रदान करता है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के लिये इसका सर्वोत्तम उपयोग करना आप पर निर्भर है। हम आशा करते हैं कि यह पत्रिका आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगी।

आपकी शानदार सफलता और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाओं सहित !

राहुल राज
(प्रबंध निदेशक)

इस अंक में .....

बिहार स्पेशल करेंट अफेयर्स 03-05

- बिहार क्लाइमेट एक्शन कॉन्क्लेव 2024
- बरौनी में हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड संयंत्र का उद्घाटन
- मुजफ्फरपुर - मोतिहारी एलपीजी पाइपलाइन
- बिहार दिवस 2024
- बिहार में कालूघाट IWT टर्मिनल का उद्घाटन

राष्ट्रीय परिदृश्य 06-09

- 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट
- नई इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति 2024
- N I A के विशेष डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम (CCMS) का उद्घाटन
- पीएम-सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना
- उन्नति (उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगीकरण) योजना
- महतारी वंदन योजना
- उल्लास - नव भारत साक्षरता कार्यक्रम

आर्थिक परिदृश्य 10-14

- नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NUCFDC)
- 'ई-किसान उपज निधि' (डिजिटल गेटवे)
- CFQCTI पोर्टल का शुभारंभ
- स्टार्टअप महाकुंभ 2024
- भारत रोजगार रिपोर्ट 2024
- फाइनेंसिंग एग्रोकेमिकल रिडक्शन एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम (FARM)
- कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र (ICCC)
- खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024

वैश्विक परिदृश्य 15-17

- भारत-ईएफटीए व्यापार एवं आर्थिक साझीदारी समझौता
- भारत-मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा
- भारत-प्रशांत आर्थिक ढांचा (IPEF) की मंत्रिस्तरीय बैठक
- ऑपरेशन इंद्रावती

विज्ञान और प्रौद्योगिकी 18-21

- डीआरडीओ का 'मिशन दिव्यास्त्र'
- भारत सेमीकंडक्टर मिशन
- इंडिया AI मिशन
- स्केलेबल इंस्ट्रक्शनल मल्टीवर्ल्ड एजेंट (SIMA)
- PSLV कक्षीय प्रायोगिक मॉड्यूल 3 (POEM 3) मिशन
- एम्युनिशन-कम-टॉरपीडो-कम-मिसाइल (ACTCM) बार्ज प्रोजेक्ट

भूगोल, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 22-25

- भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट
- अगलेगा (Agalega) द्वीपसमूह
- इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA)
- विश्व वन्यजीव दिवस 2024
- सेला सुरंग (Sela Tunnel)
- ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2024
- टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन (TWS)

अन्य सुर्खियाँ 26-31

- ए.एस. राजीव सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त
- अभ्यास 'भारत शक्ति'
- कोचरब आश्रम का उद्घाटन
- पीएम-सूरज पोर्टल
- लैंगिक असमानता सूचकांक 2022
- अभ्यास टाइगर ट्राइंफ - 24
- नई दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर
- सरस्वती सम्मान 2023
- ग्रिड-इंडिया को मिनीरत्न कंपनी का दर्जा
- भारत टीबी रिपोर्ट 2024
- विश्व क्षय रोग दिवस-2024
- विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024
- अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 का समापन
- ईसीआई राष्ट्रीय पीडब्ल्यूडी आइकन
- "सुभाष अभिनंदन" का उद्घाटन

करेंट अफेयर्स आधारित प्रश्न 32

बिहार स्पेशल करेंट अफेयर्स

बिहार क्लाइमेट एक्शन कॉन्क्लेव 2024

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार क्लाइमेट एक्शन कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया ।
- इस अवसर पर देश में अपनी तरह के पहले "बिहार के लिए जलवायु लचीला और कम कार्बन विकास मार्ग" के मसौदे का अनावरण किया गया। यह कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन के खिलाफ देश की लड़ाई में एक अग्रणी रणनीति के रूप में कार्य करेगा।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- यह कॉन्क्लेव केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं था बल्कि एक ऐसा मंच था जहां परिवर्तनकारी परियोजनाओं को जनता के सामने पेश किया गया था। इनमें से, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र सबसे अलग है, जो गंगा डॉल्फ़िन के संरक्षण के लिए समर्पित है। यह एक ऐसा कदम है जो बिहार को भारत और एशिया में वन्यजीव संरक्षण में सबसे आगे रखता है।

- गौरतलब है कि दो साल पहले, बिहार सरकार ने "जलवायु-लचीला और कम-कार्बन विकास मार्ग" नामक एक महत्वाकांक्षी रणनीति विकास परियोजना के माध्यम से 2070 तक शुद्ध शून्य हासिल करने के साथ-साथ अपने लोगों और प्रणालियों की जलवायु लचीलापन बनाने की यात्रा शुरू की थी।
- बिहार क्लाइमेट एक्शन कॉन्क्लेव का आयोजन विश्व संसाधन संस्थान (WRI) भारत द्वारा UNEP और शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन के साथ-साथ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार और बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से किया गया।
- यह बिहार की महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाइयों पर चर्चा को सुविधाजनक बनाने का भी प्रयास करता है, जिसमें नेट जीरो, मुख्यधारा के जलवायु-अनुकूल विकास की ओर बढ़ने की रणनीति, जलवायु वित्त अवसरों की खोज और एक नई परिवर्तनकारी जलवायु शासन संरचना शुरू करना शामिल है।
- ये प्रयास जलवायु कार्रवाई के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने और सुझाई गई रणनीतियों को लागू करके इसके विकास पथ को तेज करने की दिशा में केंद्रित हैं।
- इस कार्यक्रम का मुख्य विषय है- जलवायु परिवर्तन, तैयारी और अनुकूलन, जलवायु शमन और संक्रमण, जलवायु वित्त और सह-लाभ, बिहार की हरित क्षमता को अनलॉक करना ।
- इस कार्यक्रम का अपेक्षित परिणाम है -
  (i) बिहार में जलवायु कार्रवाई के लिए मजबूत साझेदारी और नेटवर्क।
  (ii) जलवायु पहलों को लागू करने के लिए हितधारकों के बीच जागरूकता और क्षमता में वृद्धि।

बरौनी में हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड संयंत्र का उद्घाटन

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बरौनी में हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) का उद्घाटन किया। यह संयंत्र किसानों को किफायती यूरिया प्रदान करेगा और उनकी उत्पादकता एवं वित्तीय स्थिरता में वृद्धि करेगा।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- बरौनी में हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) उर्वरक संयंत्र 9500 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित हुआ। सरकार ने हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) को 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष (एलएमटीपीए) की यूरिया उत्पादन क्षमता के साथ 9512 करोड़ रु. के अनुमानित निवेश के साथ बरौनी इकाई को पुनर्जीवित करने का आदेश दिया था ।
- हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) के बरौनी उर्वरक संयंत्र ने अक्टूबर 2022 में यूरिया उत्पादन शुरू किया। अत्याधुनिक गैस आधारित बरौनी संयंत्र, यूरिया क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) और हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल) की बंद पड़ी यूरिया इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार द्वारा की गई पहल का हिस्सा है।

हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के बारे में

- 15 जून, 2016 को निगमित की गई हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), एनटीपीसी लिमिटेड (एनटीपीसी), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) और एफसीआईएल/एचएफसीएल की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसे अनुमानित तौर पर 25,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी इकाइयों को पुनर्जीवित करने का काम सौंपा गया है।
- एचयूआरएल के सभी तीन संयंत्रों की शुरुआत से देश में 38.1 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष (एलएमटीपीए) स्वदेशी यूरिया उत्पादन बढ़ेगा और यूरिया उत्पादन में भारत को 'आत्मनिर्भर' बनाने के प्रधानमंत्री के स्वप्न को साकार करने में सहायता मिलेगी। यह परियोजना न केवल किसानों के लिए उर्वरक की उपलब्धता में सुधार करेगी बल्कि देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के अलावा सड़क, रेलवे, सहायक उद्योग आदि जैसे बुनियादी ढांचे के विकास सहित क्षेत्र में भी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी।
- हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) संयंत्र में विभिन्न अनूठी विशेषताएं हैं, जैसे वितरित नियंत्रण प्रणाली (डीसीएस), आपातकालीन शटडाउन प्रणाली (ईएसडी) और पर्यावरण निगरानी प्रणाली आदि से सुसज्जित अत्याधुनिक ब्लास्ट प्रूफ नियंत्रण कक्ष। इसमें 65 मीटर लंबाई और 2 मीटर ऊंचाई का भारत का पहला वायु संचालित बुलेट प्रूफ रबर बांध भी है।
- यह सुविधा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्यों में यूरिया की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से दुनिया की विश्व प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करती है। यूरिया आपूर्ति के अलावा, यह परियोजना विनिर्माण इकाई अपने आसपास के छोटे और मध्यम स्तर के उद्योगों / विक्रेताओं के विकास में भी मदद करेगी।
- संयंत्रों के संचालन से देश यूरिया उर्वरक के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा, आयात कम होने से विदेशी मुद्रा की बचत होगी और यह "उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत" की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।

मुजफ्फरपुर - मोतिहारी एलपीजी पाइपलाइन

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में प्रधानमंत्री ने 109 किमी लंबी इंडियन ऑयल की मुजफ्फरपुर - मोतिहारी एलपीजी पाइपलाइन का उद्घाटन किया।
- नया पाइपलाइन टर्मिनल नेपाल को पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात के लिए एक रणनीतिक आपूर्ति बिंदु के रूप में भी कार्य करेगा जो बिहार राज्य और पड़ोसी देश नेपाल में स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन तक पहुंच प्रदान करेगी।
- यह उत्तर बिहार के 8 जिलों यानी पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढी और मधुबनी को सेवा प्रदान करेगा।
- इसके अलावा मोतिहारी में इंडियन ऑयल के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट और स्टोरेज टर्मिनल को राष्ट्र को समर्पित किया जो मोतिहारी प्लांट से जुड़े खाद्य बाजारों में आपूर्ति श्रृंखला को भी सुचारू बनाएगा।

गैस पाइपलाइन क्या होता है?

- गैस पाइपलाइन प्राकृतिक गैस के लम्बी दूरियों के परिवहन के लिए एक किफायती और सुरक्षित तरीका है।
- देश के सभी हिस्सों में प्राकृतिक गैस की पर्याप्त उपलब्धता और समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए एक इंटरकनेक्टेड राष्ट्रीय गैस ग्रिड (National Gas Grid) का निर्माण किया गया है। गैस पाइपलाइन का नेटवर्क गैस बाजार की संरचना और उसके विकास को निर्धारित करता है।
- वर्तमान में, देश में लगभग 17000 किमी लंबा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क कार्यरत है। इसके अलावा देश भर में प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराने के लिए लगभग 15,500 किलोमीटर अतिरिक्त पाइपलाइन विकसित किया जा रहा है जिसका विकास विभिन्न चरणों में होना है।
- इससे सभी क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस की आसान उपलब्धता सुनिश्चित होगी और संभावित रूप से समान आर्थिक और सामाजिक प्रगति हासिल करने में भी मदद मिलेगी।
- ध्यातव्य है कि गेल एलपीजी ट्रांसमिशन के लिए पाइपलाइनों का स्वामित्व और संचालन करने वाली भारत की पहली कंपनी है। इसमें 2040 किलोमीटर का एलपीजी पाइपलाइन नेटवर्क है, जिसमें से 1,427 किलोमीटर का नेटवर्क भारत के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों को जोड़ता है और 610 किलोमीटर का नेटवर्क देश के दक्षिणी हिस्से में पूर्वी तट को जोड़ता है।

बिहार दिवस 2024

सुर्खियों में क्यों?

- भारत में हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- यह दिवस 1912 में बिहार राज्य की स्थापना की वर्षगांठ का प्रतीक है। बिहार राज्य पहले बंगाल प्रेसीडेंसी का हिस्सा था।
- गौरतलब है कि 22 मार्च, 1912 बंगाल से अलग करके बिहार को एक अलग राज्य बनाया गया।

- ध्यान रहे, पहला बिहार दिवस कार्यक्रम राज्य की 111वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 2010 में आयोजित किया गया था।
- वर्ष 1936 में बिहार से ओड़िशा को एवं वर्ष 2000 में झारखण्ड को अलग किया गया है ।
- बिहार दिवस का महत्व बिहार के समृद्ध इतिहास, संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करने में निहित है।

बिहार में कालूघाट IWT टर्मिनल का उद्घाटन

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने बिहार के बेतिया में कालूघाट अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल (IWT) और दो सामुदायिक घाटों का उद्घाटन किया।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- कालूघाट बिहार के सारण जिले में गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है, जो इस क्षेत्र के परिवहन नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में उभर रहा है।
- यह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-19 तक अपनी सीधी पहुंच के साथ, टर्मिनल कार्गो आवाजाही के लिए, विशेष रूप से रक्सौल और उत्तरी बिहार के भीतरी इलाकों के माध्यम से नेपाल जाने वाले शिपमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण संपर्क के रूप में कार्य करता है।
- इसके अलावा, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या-37 के माध्यम से नेपाल और भारत को जोड़ने के लिए गंडक नदी पर मंगलपुर और बेतिया में फ्लोटिंग पोंटून घाट स्थापित किए गए हैं, जो 3.33 करोड़ रुपये के निवेश से तैयार हुआ है।

- ध्यातव्य है कि जल मार्ग विकास परियोजना के एक भाग के रूप में, भारतीय अंतर्गेशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) ने राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या-1 के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन (IWT) ईकोसिस्टम के विकास की शुरुआत की है। इसके तहत नौवहन के निर्माण के साथ-साथ कार्गो हैंडलिंग, निर्बाध नौवहन के लिए फ़ेयरवे विकास करना, रात्रि नौवहन और आरआईएस सुविधाओं के प्रावधान के लिए मल्टीमॉडल टर्मिनलों (एमएमटीएस) और इंटरमॉडल टर्मिनलों (आईएमटीएस) के निर्माण की जाएगी।
- गौरतलब है कि सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत जलमार्गों की क्षमता को उजागर करने के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के अंतर्गत 111 (5 मौजूदा और 106 नए) राष्ट्रीय जलमार्गों (एनडब्ल्यू) की घोषणा शामिल है।

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में देश में एक साथ चुनाव कराये जाने के संदर्भ में गठित उच्चस्तरीय समिति (एचएलसी) ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु को अपनी रिपोर्ट सौंपी।
- उल्लेखनीय है कि पूर्व राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर एक उच्चस्तरीय समिति का गठन 2 सितंबर, 2023 को किया गया था।

रिपोर्ट से संबंधित प्रमुख बिंदु

- सभी सुझावों और दृष्टिकोणों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, समिति ने एक साथ चुनाव कराने के लिए दो-चरणीय दृष्टिकोण की सिफारिश की है। पहले चरण में, लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के लिए एक साथ चुनाव होंगे। दूसरे चरण में, नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव को लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के साथ इस तरह से समन्वित किया जाएगा कि नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव लोकसभा के चुनाव होने के सौ दिनों के भीतर हो जाएं।
- समिति ने यह भी सिफारिश की है कि तीनों स्तरों के चुनावों में उपयोग के लिए एक ही मतदाता सूची और चुनावी फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) होना चाहिए।
- एक साथ चुनाव कराये जाने की संभावनाओं की पड़ताल करने और संविधान के मौजूदा प्रारूप को ध्यान में रखते हुए समिति ने अपनी सिफारिशें इस तरह तैयार की हैं कि वे संविधान की भावना के अनुरूप हैं तथा उसके लिए संविधान में संशोधन करने की नाममात्र जरूरत है।
- इसकी सिफारिशों से मतदाताओं की पारदर्शिता, समावेशिता, सहजता और विश्वास में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। एक साथ चुनाव कराने से विकास प्रक्रिया और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा मिलेगा, हमारा लोकतांत्रिक ताना-बाना मजबूत होगा और भारत की आकांक्षाओं को साकार रूप प्राप्त होगा।

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' (ONE NATION ONE ELECTION) की संकल्पना क्या है?

- 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की अवधारणा एक ऐसे परिदृश्य की कल्पना करती है जहाँ प्रत्येक पाँच वर्ष पर सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव लोकसभा के आम चुनावों के साथ-साथ संपन्न होंगे।
- एक साथ चुनाव कराने का विचार, भारतीय चुनावी चक्र को इस तरह से संरचित करने को लेकर है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ एवं निश्चित समय के भीतर हों, ताकि चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जाए और चुनावों की आवृत्ति को कम किया जाए, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी।
- यह विचार वर्ष 1983 से ही अस्तित्व में है, जब निर्वाचन आयोग ने पहली बार इसे पेश किया था। हालाँकि वर्ष 1967 तक भारत में एक साथ चुनाव आयोजित कराना एक सामान्य परिदृश्य रहा था। लेकिन कार्यकाल समाप्त होने से पहले विधानसभाओं और लोकसभाओं के बार-बार भंग होने के कारण यह अभ्यास धीरे-धीरे प्रचलन से बाहर हो गया।
- वर्ष 2018 में भारत के विधि आयोग द्वारा एक साथ चुनावों पर जारी मसौदा रिपोर्ट के अनुसार, एक राष्ट्र एक चुनाव के अभ्यास से सार्वजनिक धन की बचत की जा सकती है, प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा बलों पर पड़ने वाले तनाव को कम किया जा सकेगा, सरकारी नीतियों का समय पर कार्यान्वयन होगा तथा चुनाव प्रचार के बजाय विकास गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न प्रशासनिक सुधार किये जा सकेंगे।
- लोकसभा के प्रथम आम चुनाव और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव 1951-52 में एक साथ आयोजित कराये गए थे। यह प्रक्रिया वर्ष 1957, 1962 और 1967 में आयोजित अगले तीन आम चुनावों में भी जारी रहा। वर्तमान में केवल कुछ राज्यों (आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम) की विधानसभाओं के चुनाव ही लोकसभा चुनावों के साथ होते हैं।

नई इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति 2024

सुर्खियों में क्यों?

- केंद्र सरकार ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) विनिर्माण को बढ़ावा देने और प्रमुख वैश्विक निर्माताओं द्वारा ई-वाहन क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए 15 मार्च 2024 को एक योजना को मंजूरी दी है।

नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति की मुख्य विशेषताएं

- नई नीति कंपनियों को देश में न्यूनतम 4,150 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए बाध्य करती है और उन्हें कम से कम 25% घटकों के साथ ईवी के लिए स्थानीय विनिर्माण स्थापित करने के लिए तीन साल की अनुमति देगी, जो संभावित रूप से टेस्ला की बाजार में प्रवेश योजनाओं को बढ़ावा देगी।
- निवेश प्रतिबद्धता को छोड़े गए कस्टम ड्यूटी के बदले में बैंक गारंटी द्वारा समर्थित होना होगा।
- भारत में अपना प्लांट स्थापित करने का विकल्प चुनने वाले ईवी कारोबारियों के लिए लाभ के अलावा, केंद्र कम कस्टम दर पर कारों के सीमित आयात (8000 सालाना) की अनुमति देगा।
- इसके तहत विनिर्माण के लिए समय-सीमा तय की गई। भारत में विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने के लिए न्यूनतम 3 वर्ष और अधिकतम 5 वर्षों के भीतर 50% घरेलू मूल्य संवर्धन (डीवीए) तक ई-वाहनों का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करना शामिल है।
- विनिर्माण के दौरान घरेलू मूल्य संवर्धन (डीवीए) तीसरे वर्ष तक 25% और पांचवें वर्ष तक 50% का स्थानीयकरण स्तर हासिल करना होगा।
- 15 प्रतिशत का सीमा शुल्क (जैसा कि सीकेडी इकाइयों पर लागू होता है) कुल 5 वर्ष की अवधि के लिए 35,000 अमेरिकी डॉलर और उससे अधिक के न्यूनतम सीआईएफ मूल्य वाले वाहन पर लागू होगा बशर्ते निर्माता 3 वर्ष की अवधि के भीतर भारत में विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करे।
- आयात के लिए अनुमति : ईवी की कुल संख्या पर छोड़ा गया शुल्क निवेश तक सीमित होगा या 6,484 करोड़ रुपये (पीएलआई योजना के तहत प्रोत्साहन के बराबर) जो भी कम हो।
- यदि निवेश $800 मिलियन या अधिक है, तो प्रति वर्ष 8,000 से अधिक की दर से अधिकतम 40,000 ईवी की अनुमति नहीं होगी। अप्रयुक्त वार्षिक आयात सीमाओं को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी।
- कंपनी द्वारा की गई निवेश प्रतिबद्धता को छोड़े गए कस्टम ड्यूटी के बदले में बैंक गारंटी द्वारा समर्थित होना होगा।
- योजना दिशानिर्देशों के तहत परिभाषित घरेलू मूल्य संवर्धन और न्यूनतम निवेश मानदंडों को पूरा न करने की स्थिति में बैंक गारंटी लागू की जाएगी।

NIA के विशेष डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम (CCMS) का उद्घाटन

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के विशेष डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम (CCMS) का उद्घाटन किया।
- इसके अलावा केन्द्रीय गृह मंत्री ने जम्मू और केरल स्थित NIA के दो ब्रांच ऑफिस और रायपुर में एक आवासीय परिसर का ई-उद्घाटन भी किया।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- नई CCMS प्रणाली NIA को आतंकवाद और संगठित अपराध के मामलों में बेहतर तालमेल करने में सक्षम बनाएगी जिससे न्याय व्यवस्था में सुधार आएगा। CCMS के विशेष प्रकार के नए वर्जन को NIA ने उपयोग करने वालों के अनुकूल, आसानी से तैनात होने वाले

एवं कस्टमाइज करने लायक ब्राउज़र आधारित सॉफ्टवेयर के रूप में विकसित किया है।

- इससे राज्य के पुलिस बलों को जांच के दौरान एकत्रित डेटा, जैसे- केस से जुड़े दस्तावेज़, एकत्र किए गए साक्ष्य और अदालत में पेश आरोप-पत्रों को व्यवस्थित, एकीकृत करने और डिजिटल बनाने में मदद मिलेगी।
- उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2023 में आयोजित 'आतंकवाद निरोधी सम्मेलन' के दौरान गृह मंत्री ने देशभर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करने पर ज़ोर दिया था, जो राज्य पुलिस बलों और केंद्रीय एजेंसियों को सही तरीके और तालमेल के साथ जांच पूरी करने में सक्षम बनाए।
- CCMS राज्य पुलिस के आतंकवाद-निरोधक दस्तों सहित केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच मजबूत सहयोग को बढ़ावा देगा। यह वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और अभियोजकों, दोनों द्वारा मूल्यांकन और मार्गदर्शन के लिए स्पष्ट रूपरेखा प्रदान करके पर्यवेक्षण को बढ़ावा देगा।
- यह NIA और राज्य पुलिस बलों को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता के रूप में

औपनिवेशिक युग के बाद बनाए गए नए क्रिमिनल कोड को लागू करने के लिए तैयार होने में भी मदद करेगा।

- इस अवसर पर गृह मंत्री ने तीन नए आपराधिक कानूनों पर NCRB के मोबाइल ऐप 'संकलन' को भी लॉन्च किया। तीन परिवर्तनकारी नए आपराधिक कानूनों को नेविगेट करने के लिए, एनसीआरबी ने पुराने और नए कानूनों के बीच एक सेतु के रूप में डिज़ाइन किए गए "संकलन" ऐप को तैयार किया है।
- यह ऐप एक कॉम्प्रिहेन्सिव गाइड के रूप में कार्य करेगा, जो पुराने और नए कानूनी प्रावधानों की विस्तार से तुलना करने में सक्षम है। हमारे देश की विविध प्रकार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, 'संकलन' ऐप को ऑफ़लाइन मोड में काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, इसकी उपलब्धता सुदूर इलाकों में भी सुनिश्चित की गई है, ताकि सभी हितधारकों को हर समय वांछित जानकारी प्राप्त हो सके।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) क्या है?

- NIA भारत की केंद्रीय आतंक रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है, जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करने वाले सभी अपराधों की जाँच करता है।
- इसका गठन राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) अधिनियम, 2008 के तहत किया गया था।
- एजेंसी को गृह मंत्रालय से लिखित उद्घोषणा के तहत राज्यों से विशेष अनुमति के बिना राज्यों में आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जाँच करने का अधिकार है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
- गौरतलब है कि वर्ष 2008 में 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के मद्देनज़र, NIA की स्थापना 31 दिसंबर, 2008 को अस्तित्व में आई और वर्ष 2009 में इसने अपना कामकाज शुरू किया।
- इसका उद्देश्य जांच के नवीनतम वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके अनुसूचित अपराधों की गहराई से पेशेवर जांच करना और ऐसे मानक स्थापित करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एनआईए को सौंपे गए सभी मामलों का पता लगाया जा सके।

पीएम-सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने और एक करोड़ घरों के लिए हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने हेतु 75,021 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दे दी है।
- ध्यान रहे, प्रधानमंत्री ने 13 फरवरी, 2024 को इस योजना की शुरुआत की थी।

योजना की प्रमुख विशेषताएँ

- यह योजना 2 किलोवाट क्षमता वाली प्रणाली के लिए प्रणालीगत लागत के 60 प्रतिशत और 2 से 3 किलोवाट क्षमता वाली प्रणाली के लिए अतिरिक्त प्रणालीगत लागत के 40 प्रतिशत के बराबर सीएफए प्रदान करेगी। सीएफए को 3 किलोवाट पर सीमित किया जाएगा। मौजूदा मानक कीमतों पर, इसका आशय 1 किलोवाट क्षमता वाली प्रणाली के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट क्षमता वाली प्रणाली के लिए 60,000 रुपये और 3 किलोवाट या उससे अधिक वाली प्रणाली के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी से होगा।
- परिवार राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से सब्सिडी के लिए आवेदन करेंगे और छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए एक उपयुक्त विक्रेता का चयन करने में सक्षम होंगे। राष्ट्रीय पोर्टल उचित सिस्टम आकार, लाभ कैलकुलेटर, विक्रेता रेटिंग आदि जैसी प्रासंगिक जानकारी प्रदान करके परिवारों को उनकी निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहायता करेगा।
- परिवार 3 किलोवाट तक के आवासीय आरटीएस सिस्टम की स्थापना के लिए वर्तमान में लगभग 7% के संपार्श्विक-मुक्त कम-ब्याज ऋण उत्पादों का उपयोग करने में सक्षम होंगे।
- ग्रामीण क्षेत्रों में छत पर सौर ऊर्जा अपनाने के लिए रोल मॉडल के रूप में कार्य करने के लिए देश के प्रत्येक जिले में एक मॉडल सौर गांव विकसित किया जाएगा।
- शहरी स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थान भी अपने क्षेत्रों में आरटीएस स्थापनाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन से लाभान्वित होंगे।
- यह योजना नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी (आरईएससीओ) आधारित मॉडलों के लिए भुगतान सुरक्षा के लिए एक घटक के साथ-साथ आरटीएस में नवीन परियोजनाओं के लिए एक फंड प्रदान करती है।

उन्नति (उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगीकरण) योजना

सुर्ख़ियों में क्यों?

- 09 मार्च, 2024 को अरूणाचल प्रदेश में 'विकसित भारत - विकसित उत्तर पूर्व' कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने उत्तर पूर्व के लिए नई औद्योगिक विकास योजना, उन्नति (Uttar-Purva Transformative Industrialization) की शुरुआत की।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- यह योजना उत्तर पूर्व में औद्योगिक परितंत्र को मजबूत करेगी, नए निवेश को आकर्षित करेगी, नई विनिर्माण और सेवा इकाइयों को स्थापित करने में मदद करेगी और उत्तर पूर्व के राज्यों में रोजगार को बढ़ावा देगी।
- 10,000 करोड़ रुपये की इस योजना को पूरी तरह से भारत सरकार फंड मुहैया कराएगी और इसमें उत्तर पूर्व के सभी 8 राज्यों को शामिल किया गया है।

- यह योजना अनुमोदित इकाइयों को पूंजी निवेश, ब्याज छूट और विनिर्माण तथा सेवाओं से जुड़े प्रोत्साहन के लिए सहायता प्रदान करेगी। पात्र इकाइयों के आसान एवं पारदर्शी पंजीकरण के लिए एक पोर्टल भी शुरू किया जा रहा है।
- उन्नति योजना औद्योगिक विकास को उत्प्रेरित करने और उत्तर पूर्व क्षेत्र के आर्थिक विकास में सहायता करेगी।

महतारी वंदन योजना

सुर्खियों में क्यों?

- 10 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना शुरू की और योजना के तहत पहली किश्त का वितरण किया।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- यह योजना राज्य की पात्र विवाहित महिलाओं को मासिक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के रूप में 1000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है।
- महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने, उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने, स्त्री-पुरुष समानता को बढ़ावा देने और परिवार में महिलाओं की निर्णायक भूमिका को सुदृढ़ करने के लिए इसकी परिकल्पना की गई है।
- यह योजना राज्य की सभी पात्र विवाहित महिलाओं को लाभ प्रदान करेगी जिनकी आयु 1 जनवरी 2024 तक 21 वर्ष से अधिक है। विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र होंगी। योजना से लगभग 70 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी।
- सरकार ने महतारी वंदना योजना की पहली किश्त के तहत कुल 655 करोड़ रुपये का वितरण किया।

उल्लास - नव भारत साक्षरता कार्यक्रम

सुर्खियों में क्यों?

- 17 मार्च 2024 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग (DoSEL) द्वारा 23 देशों में ULLAS - नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के भाग के रूप में फाउंडेशनल साक्षरता और संख्यात्मक मूल्यांकन परीक्षण (FLNAT) का आयोजन किया गया।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- इस कार्यक्रम के तहत FLNAT का आयोजन राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के सभी जिलों में किया किया गया, जिसमें परीक्षा केंद्र के रूप में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (DIET) और सरकारी/सहायता प्राप्त स्कूल को शामिल किया गया।
- मूल्यांकन में तीन विषय शामिल हैं - पढ़ना, लिखना और संख्यात्मकता। यह परीक्षण पंजीकृत गैर-साक्षर शिक्षार्थियों की मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल का मूल्यांकन करने के लिए विकसित किया गया है।
- उल्लास - नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के हिस्से के रूप में आयोजित शिक्षण-शिक्षण सत्रों के प्रभाव का आकलन करने में यह परीक्षण महत्वपूर्ण है।
- FLNAT विकसित भारत और जन जन साक्षर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है।

नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (उल्लास) के बारे में

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुसार, भारत सरकार ने 2022 से 2027 तक पांच साल की अवधि के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की, जिसे ULLAS (समाज में सभी के लिए आजीवन सीखने की समझ) के नाम से जाना जाता है।
- योजना का प्राथमिक उद्देश्य 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वयस्कों को सशक्त बनाना है, जिन्हें खुद को शिक्षित करने का अवसर नहीं मिला है, और उन्हें देश के विकास में योगदान करने में सक्षम बनाना है।
- यह न केवल शिक्षार्थियों को पढ़ने, लिखने और संख्यात्मक कौशल हासिल करने की अनुमति देता है, बल्कि आजीवन सीखने को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें महत्वपूर्ण जीवन कौशल की समझ के साथ समृद्ध भी करता है।
- उल्लास शिक्षा और व्यक्तिगत विकास के मार्ग को रोशन करते हुए आशा की किरण के रूप में कार्य करना जारी रखता है।
- यह पहल राष्ट्र निर्माण के लिए कार्यात्मक साक्षरता, व्यावसायिक कौशल, वित्तीय साक्षरता, कानूनी साक्षरता, डिजिटल साक्षरता और नागरिकों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
- यह पहल स्वयंसेवा के माध्यम से संचालित होती है । यह स्वयंसेवकों को राष्ट्र-निर्माण की दिशा में कर्तव्य या कर्तव्य बोध में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है । छात्र स्वयंसेवकों को स्कूल/विश्वविद्यालय में क्रेडिट और प्रमाण पत्र, प्रशंसा पत्र और अभिनंदन सहित अन्य माध्यमों से प्रोत्साहित किया जाएगा।

उल्लास
ULLAS
नव भारत साक्षरता कार्यक्रम

नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NUCFDC)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NUCFDC) का उद्घाटन किया।

NUCFDC से संबंधित प्रमुख बिंदु

- NUCFDC शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है। यह क्षेत्र के लिए एक स्व-नियामक संगठन के रूप में भी काम करेगा।
- इसका उद्देश्य सहकारी बैंकों के लिए विशेष कार्यों और सेवाओं को सुनिश्चित करना, बैंकों और नियामकों के बीच संचार की सुविधा प्रदान करना और शहरी सहकारी बैंकों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है।
- साथ ही शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक और मजबूत बनाना है, जिससे बैंकों और उनके ग्राहकों दोनों को लाभ होगा।
- इसे गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी के रूप में काम करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है

शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के बारे में

- यूसीबी को संबंधित राज्य के राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम या बहु राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत किया जाता है।
- उन्हें संबंधित राज्य के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आरसीएस) या केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) द्वारा, जैसा भी मामला हो, विनियमित और पर्यवेक्षण किया जाता है।
- वे मुख्य रूप से भारत के शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में काम करते हैं।
- ये संस्थाएँ छोटे व्यवसायों, व्यक्तियों और समुदायों की बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। सेवाओं में जमा खाते, ऋण, प्रेषण और अन्य वित्तीय उत्पाद और सेवाएँ शामिल हैं।
- वर्तमान में, भारत में 1,500 से अधिक अनुसूचित और गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक हैं।

'ई-किसान उपज निधि' (डिजिटल गेटवे)

सुर्खियों में क्यों?

- केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, वाणिज्य और उद्योग और कपड़ा मंत्री, श्री पीयूष गोयल ने 4 मार्च 2024 को नई दिल्ली में वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (WDRA) की 'ई-किसान उपज निधि' (डिजिटल गेटवे) लॉन्च की।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- 'ई-किसान उपज निधि' पहल प्रौद्योगिकी की मदद से किसानों के भंडारण रसद (warehousing logistics) को आसान बनाएगी और किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य प्राप्त करने में सहायता करेगी।
- डिजिटल गेटवे पहल खेती को आकर्षक बनाने के हमारे प्रयास में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- 'ई-किसान उपज निधि' बिना किसी कोलेटरल, अतिरिक्त सुरक्षा जमा नीति के किसानों द्वारा संकटपूर्ण बिक्री को रोक सकती है, जिन्हें अक्सर फसल के बाद भंडारण के खराब अवसरों के कारण अपनी पूरी फसल सस्ती दरों पर बेचनी पड़ती है।
- यह पहल अपनी सरलीकृत डिजिटल प्रक्रिया के साथ किसानों के लिए किसी भी पंजीकृत WDRA गोदाम में 6 महीने की अवधि के लिए 7% प्रति वर्ष ब्याज पर भंडारण की प्रक्रिया को आसान बना सकती है।
- 'ई-किसान उपज निधि' और ई-नाम के द्वारा किसान बाजार से परस्पर जुड़े तकनीक का उपयोग करने में सक्षम होंगे जो उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सरकार को अपनी उपज बेचने से ऊपर और परे लाभ पहुंचाता है।

CFQCTI पोर्टल का शुभारंभ

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की चार महत्वपूर्ण पहलों- मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल एवं मोबाइल एप्लिकेशन, स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम, कृषि सखी अभिसरण कार्यक्रम एवं उर्वरक नमूना परीक्षण के लिए सीएफक्यूसीटीआई (केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान) के पोर्टल का शुभारंभ किया गया।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि सीएफक्यूसीटीआई पोर्टल को वर्ष 2014-15 में बंदरगाहों पर आयातित उर्वरकों के नमूने लेने, नमूनों की सिस्टम कोडिंग/डिकोडिंग व आयातकों को सीधे ऑनलाइन विश्लेषण रिपोर्ट भेजने के उद्देश्य से तैयार किया गया, ताकि किसानों को आपूर्ति से पहले उनके उत्पाद की गुणवत्ता जानने में होने वाले विलंब से बचाया जा सकें। लेकिन वर्तमान में इस पोर्टल को नया रूप दिया गया है।
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल और मोबाइल एप को नया रूप दिया गया है, जिसके तहत राष्ट्रीय, राज्य, जिला व ग्राम स्तर पर केंद्रीकृत डैशबोर्ड उपलब्ध कराया गया है। पोर्टल में मृदा रजिस्ट्री, उर्वरक प्रबंधन, इमोजी आधारित मृदा स्वास्थ्य कार्ड, पोषक तत्व डैशबोर्ड, पोषक तत्वों के हीट मैप दिए गए हैं। अब तत्काल प्रगति की निगरानी की जा सकती है।
- स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के 20 केंद्रीय व नवोदय विद्यालयों में मृदा प्रयोगशालाएं स्थापित, अध्ययन मॉड्यूल विकसित किए और छात्रों-शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। मोबाइल एप को स्कूल कार्यक्रम के लिए अनुकूलित किया गया और पोर्टल में कार्यक्रम के लिए अलग खंड है, जहां छात्रों की गतिविधियों को रखा गया है। अब, इस कार्यक्रम को 1000 स्कूलों में बढ़ाया गया है।
- इसके तहत नाबार्ड के जरिये कृषि मंत्रालय स्कूलों में मृदा लैब्स स्थापित करेगा। यह कार्यक्रम विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग करने, मृदा नमूनों का विश्लेषण करने और मृदा में उपस्थित आकर्षक जैव विविधता के विषय में जानकारी जुटाने का अवसर प्रदान करेगा।
- कृषि मंत्रालय व ग्रामीण विकास मंत्रालय के बीच अभिसरण पहल के रूप में कृषि सखी अभिसरण कार्यक्रम को 30 अगस्त 2023 को एमओयू किया गया था। इसके एक हिस्से के रूप में 70 हजार कृषि सखियों को "पैरा-एक्सटेंशन वर्कर" के रूप में प्रमाणित करने के लिए संयुक्त पहल के रूप में कृषि सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। कृषि सखी, अर्थात स्टेट रूरल लाइवहुड मिशन द्वारा चिह्नित गांवों की महिलाओं को सहज क्षमता तथा खेती-गांवों से मजबूत जुड़ाव से ग्रामीण कृषि सेवाओं में व्याप्त अंतर को पाटने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। कृषि सखी,जनभागीदारी रूप में प्राकृतिक खेती, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, परीक्षण पर जागरूकता सृजन बैठकों का आयोजन करेगी।
- किसानों को गुणवत्तापूर्ण उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं उत्पादन, आपूर्ति और वितरण पर नियंत्रण करने की दृष्टि से कृषि मंत्रालय द्वारा केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान (सीएफक्यूसीटीआई) प्रयोगशाला स्थापित की गई। इसका लक्ष्य आयातित उर्वरकों की गुणवत्ता को नियंत्रित करना है।

स्टार्टअप महाकुंभ 2024

सुर्खियों में क्यों?

- स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदर्शित करने वाले सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक, तीन दिवसीय स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन 18-20 मार्च 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- स्टार्टअप महाकुंभ, एक अग्रणी स्टार्टअप कार्यक्रम है जो ASSOCHAM, NASSCOM, बूटस्ट्रैप इनक्यूबेशन एंड एडवाइजरी फाउंडेशन, TiE और इंडियन वेंचर एंड अल्टरनेट कैपिटल एसोसिएशन (IVCA) द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
- यह कार्यक्रम उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एसआईडीबीआई), गवर्नमेंट-ई-मार्केटप्लेस (जीईएम), एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (ईसीजीसी) और ज़ोमैटो द्वारा समर्थित है।

- स्टार्टअप महाकुंभ की थीम 'भारत इनोवेट्स' है जो नवाचार और स्टार्टअप के बीच जटिल संबंध को दिखाती है। यह आयोजन इनोवेशन के क्षेत्र में भारत की प्रतिष्ठा को मजबूत करेगा और देश के वैश्विक स्टार्टअप फुटप्रिंट को बढ़ाएगा।
- इस स्टार्टअप इवेंट का उद्देश्य उद्यम पूंजीपतियों, निवेशकों और संभावित कॉर्पोरेट भागीदारों सहित आविष्कारकों के एक स्पेक्ट्रम के साथ स्टार्टअप को जोड़ना है।

- इस कार्यक्रम में एआई, बी2बी, एग्रीटेक, डीपटेक, क्लाइमेट टेक, गेमिंग, ईस्पोर्ट्स, फिनटेक, इनक्यूबेटर और एक्सेलेरेटर पर मंडप सहित सेक्टर-केंद्रित मंडप होंगे।
- मेगा स्टार्टअप इवेंट विचारों के आदान-प्रदान के लिए एक मंच के रूप में भी काम करेगा जो भारत में एक मजबूत और लचीला स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में योगदान देगा। यह उद्देश्य परामर्श सत्र, मास्टरक्लास, मुख्य भाषण और यूनिकॉर्न गोलमेज सम्मेलन सहित कई गतिविधियों के माध्यम से पूरा किया जाएगा।
- इस कार्यक्रम में वीसी, एंजेल इन्वेस्टर्स, फैमिली ऑफिसेज और एचएनआई जैसे आविष्कारकों के साथ-साथ संभावित कॉर्पोरेट भागीदारों के साथ स्टार्टअप को जोड़ने के उद्देश्य से, इस कार्यक्रम में 1000 से ज्यादा स्टार्टअप, 10 से ज्यादा थीमेटिक ट्रैक्स, 1000 से ज्यादा इन्वेस्टर्स, 500 से ज्यादा इनक्यूबेटर्स और एक्सेलेरेटर्स, 5000 से ज्यादा सम्मेलन प्रतिनिधियों, 10 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधिमंडल, 5000 से ज्यादा भविष्य के उद्यमियों और तीन दिनों की अवधि में 40,000 से ज्यादा व्यावसायिक विजिटर्स की मेजबानी की उम्मीद है।

भारत रोजगार रिपोर्ट 2024

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) और मानव विकास संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 प्रकाशित की गई ।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत के युवा बढ़ती बेरोजगारी दर से जूझ रहे हैं, लगभग 83 प्रतिशत बेरोजगार आबादी इस जनसांख्यिकीय से संबंधित है।

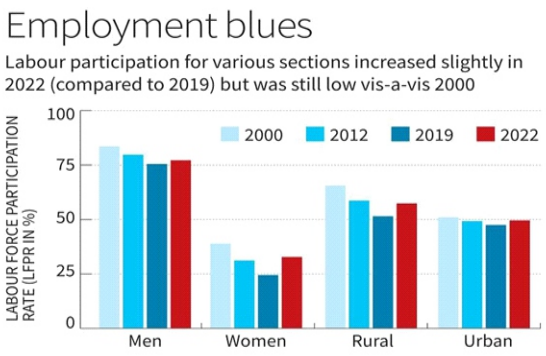

संबंधित प्रमुख बिंदु

- रिपोर्ट एक चिंताजनक प्रवृत्ति को रेखांकित करती है जहां कुल बेरोजगार युवाओं में कम से कम माध्यमिक शिक्षा प्राप्त शिक्षित युवाओं का अनुपात वर्ष 2000 में 35.2 प्रतिशत से लगभग दोगुना होकर 2022 में 65.7 प्रतिशत हो गया है।
- रिपोर्ट के अनुसार, उच्च शिक्षा में बढ़ते नामांकन के बावजूद, गुणवत्ता संबंधी चिंताएँ बनी हुई हैं, स्कूल और उच्च शिक्षा स्तरों पर बच्चों में सीखने की कमी देखी गई है।
- अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2000 और 2019 के बीच युवा रोजगार और अल्परोजगार में वृद्धि हुई, लेकिन COVID-19 महामारी के वर्षों के दौरान इसमें गिरावट देखी गई। हालाँकि, शिक्षित युवाओं ने इस अवधि के दौरान काफी उच्च स्तर की बेरोजगारी का अनुभव किया।
- श्रम बल भागीदारी दर (LFPR), श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR), और बेरोजगारी दर (UR) में वर्ष 2000 और 2018 के बीच निरंतर गिरावट देखी गई, केवल वर्ष 2019 के बाद सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है।
- मजदूरी काफी हद तक स्थिर रही है या गिरावट आई है, नियमित श्रमिकों और स्व-रोज़गार व्यक्तियों के लिए वास्तविक मजदूरी में 2019 के बाद नकारात्मक प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। अकुशल आकस्मिक श्रमिकों के एक बड़े हिस्से को 2022 में अनिवार्य न्यूनतम मजदूरी नहीं मिली।
- विभिन्न राज्यों में रोजगार परिणामों में महत्वपूर्ण भिन्नताएं मौजूद हैं, कुछ राज्य रोजगार संकेतकों में लगातार निचले स्थान पर हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य पिछले कुछ वर्षों में खराब रोजगार परिणामों से जूझ रहे हैं, जो क्षेत्रीय नीतियों के प्रभाव को दर्शाता है।
- समग्र श्रम बाजार संकेतकों की प्रवृत्ति महिला श्रम बाजार में अधिक प्रमुखता से प्रतिध्वनित होती है। पिछले वर्षों में उल्लेखनीय गिरावट के बाद, महिला श्रम बाजार भागीदारी दर ने 2019 के बाद से, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से ऊपर की ओर प्रक्षेपवक्र प्रदर्शित किया।
- कृषि रोजगार से दूर जाने की धीमी गति में 2019 के बाद उलटफेर देखा गया, कृषि रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और गैर-कृषि रोजगार में गिरावट आई, खासकर विनिर्माण क्षेत्र में।
- रिपोर्ट व्यापक आजीविका असुरक्षाओं को रेखांकित करती है, विशेष रूप से उन लोगों के बीच जो सामाजिक सुरक्षा उपायों के अंतर्गत नहीं आते हैं।
- शहरीकरण और प्रवासन दरों में वृद्धि का अनुमान है, अनुमान के अनुसार 2030 तक प्रवासन दर लगभग 40 प्रतिशत होगी और प्रवासन के कारण पर्याप्त शहरी जनसंख्या वृद्धि होगी, विशेष रूप से पूर्वी और मध्य क्षेत्रों से दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों में।
- रिपोर्ट महिला श्रम बल भागीदारी की कम दर के साथ श्रम बाजार में बढ़ते लिंग अंतर पर भी प्रकाश डालती है। युवा महिलाओं, विशेषकर उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाओं को रोजगार हासिल करने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- सकारात्मक कार्रवाई और लक्षित नीतियों के बावजूद सामाजिक असमानताएँ भी बनी हुई हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को बेहतर नौकरी के अवसरों तक पहुँचने में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। यद्यपि सभी समूहों में शैक्षिक उपलब्धि में सुधार हुआ है, सामाजिक पदानुक्रम कायम है, जिससे रोजगार असमानता बढ़ गई है।

फाइनेंसिंग एग्रोकेमिकल रिडक्शन एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम (FARM)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में फाइनेंसिंग एग्रोकेमिकल रिडक्शन एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम में इक्वाडोर, भारत, केन्या, लाओस, फिलीपींस, उरुग्वे और वियतनाम ने भाग लिया।
- गौरतलब है कि वैश्विक पर्यावरण सुविधा द्वारा वित्त पोषित, कार्यक्रम का नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन और अफ्रीकी विकास बैंक के सहयोग से यूएनईपी द्वारा किया जाता है।

FARM के बारे में

- फाइनेंसिंग एग्रोकेमिकल रिडक्शन एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम (FARM) एग्रोकेमिकल प्रदूषण से निपटने के लिए $379 मिलियन बजट के साथ पांच साल की पहल है।
- वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) से वित्तीय सहायता के साथ संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) के नेतृत्व में फाइनेंसिंग

एग्रोकेमिकल रिडक्शन एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम, बैंकों और नीति-निर्माताओं के लिए व्यावसायिक मामले को फिर से तैयार करने के लिए विस्तार से बताता है। किसानों के प्रति नीति और वित्तीय संसाधन को सुलभ बनाता है, ताकि उन्हें जहरीले कृषि रसायनों के लिए कम और गैर-रासायनिक विकल्प अपनाने में मदद मिल सके और बेहतर प्रथाओं की ओर बदलाव की सुविधा मिल सके।

- पांच साल के कार्यक्रम में 51,000 टन से अधिक खतरनाक कीटनाशकों और 20,000 टन से अधिक प्लास्टिक कचरे को निकलने से रोकने का अनुमान है, जबकि 35,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से बचने और 30 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को क्षरण से बचाने का अनुमान है। खेतों और किसानों के लिए कम-रासायनिक और गैर-रासायनिक विकल्प प्रदान करता है।
- एफएआरएम कार्यक्रम प्रभावी कीट नियंत्रण, उत्पादन विकल्पों और स्थायी उपज में व्यापार की उपलब्धता में सुधार के लिए बैंकिंग, बीमा और निवेश मानदंडों को मजबूत करते हुए पीओपी युक्त कृषि रसायनों और कृषि-प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और बेहतर प्रबंधन मानकों को अपनाने के लिए सरकारी विनियमन का समर्थन करेगा।
- FARM कार्यक्रम के उद्घाटन में सभी सात देशों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया, जिसमें सार्वजनिक और निजी बैंकों, नीति निर्माताओं, किसान सहकारी समितियों, खुदरा विक्रेता, कृषि रसायन और प्लास्टिक निर्माताओं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, नागरिक समाज, शिक्षाविदों और कार्यक्रम में सीधे तौर पर शामिल 100 से अधिक भागीदार और हितधारक शामिल थे।
- यह कार्यक्रम कृषि प्रदूषण से निपटने के लिए सरकारों, वित्तीय संस्थानों, किसानों और निर्माताओं के बीच सहयोगात्मक प्रयासों में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, जो अधिक न्यायसंगत और लचीली खाद्य प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करता है।

कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र (ICCC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली के कृषि भवन में कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (ICCC) का उद्घाटन किया। यह कृषि क्षेत्र में डिजिटल नवाचारों को प्रदर्शित करने वाले एक व्यापक डैशबोर्ड के रूप में कार्य करता है, जो कृषि पद्धतियों को आगे बढ़ाने में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर जोर देता है।

ICCC के बारे में

- ICCC एक तकनीक-आधारित समाधान है जिसमें कई आईटी एप्लिकेशन और प्लेटफ़ॉर्म शामिल हैं, जिसे सूचित निर्णय लेने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- यह केंद्र कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में स्थित है, जो कृषि क्षेत्र में कानून, नीति निर्माण और पहल के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।
- आईसीसीसी तापमान, वर्षा, हवा की गति, फसल की पैदावार और उत्पादन अनुमानों पर बड़ी मात्रा में दानेदार डेटा एकत्र करने और संसाधित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करता है और प्रस्तुत करता है। यह ग्राफिकल प्रारूप में है।

- ICCC रिमोट सेंसिंग सहित कई स्रोतों से प्राप्त भू-स्थानिक जानकारी को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराकर कृषि क्षेत्र की व्यापक निगरानी को सक्षम करेगा। यह मृदा सर्वेक्षण के माध्यम से प्राप्त प्लॉट-स्तरीय डेटा; भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) से मौसम डेटा; डिजिटल फसल सर्वेक्षण से बुआई डेटा; कृषि मैपर से किसान और खेत से संबंधित डेटा, भूमि की जियो-फेंसिंग और जियो-टैगिंग के लिए एक एप्लिकेशन; कृषि सांख्यिकी के लिए एकीकृत पोर्टल (यूपीएजी) से बाजार खुफिया जानकारी; और सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (जीसीईएस) से उपज अनुमान डेटा उपलब्ध कराएगा।
- डेटा का एकीकृत विज़ुअलाइज़ेशन ICCC पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा त्वरित और कुशल निर्णय लेने में सक्षम होगा, जिसे आगे चलकर पीएम-किसान चैटबॉट के साथ जोड़ा जा सकता है।

खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) और WRAP (अपशिष्ट और संसाधन कार्रवाई कार्यक्रम) ने संयुक्त रूप से खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 प्रकाशित की है।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- रिपोर्ट "खाद्य अपशिष्ट" को "मानव खाद्य आपूर्ति श्रृंखला से हटाए गए भोजन और संबंधित अखाद्य भागों" के रूप में परिभाषित करती है। दूसरी ओर, "खाद्य हानि" को "सभी फसल और पशुधन मानव-खाद्य वस्तु माला" के रूप में परिभाषित किया गया है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कटाई के बाद/वध उत्पादन/आपूर्ति श्रृंखला से पूरी तरह से बाहर निकल जाते हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस (30 मार्च) से पहले जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2022 में, 1.05 बिलियन टन खाद्य अपशिष्ट (अखाद्य भागों सहित) उत्पन्न हुआ था, जो प्रति व्यक्ति 132 किलोग्राम और लगभग पांचवां हिस्सा उपभोक्ताओं के लिए सभी खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं।
- दुनिया भर में परिवारों ने 2022 में एक दिन में एक अरब से अधिक भोजन बर्बाद किया, जबकि 783 मिलियन लोग भूख से जूझ रहे थे और मानवता के एक तिहाई हिस्से को खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा।
- रिपोर्ट में खाद्य अपशिष्ट की ट्रैकिंग और निगरानी को सक्षम करने के लिए डेटा बुनियादी ढांचे के विस्तार और मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि " 2030 तक भोजन की बर्बादी, विशेषकर खुदरा और खाद्य सेवाओं में कई निम्न और मध्यम आय वाले देशों में सतत विकास लक्ष्य 12.3 को पूरा करने के लिए प्रगति पर नज़र रखने के लिए पर्याप्त प्रणालियों का अभाव है।
- लोकप्रिय धारणा के विपरीत, भोजन की बर्बादी एक 'अमीर देश की समस्या' नहीं थी, रिपोर्ट में कहा गया है, उच्च आय, उच्च-मध्यम और निम्न-मध्यम आय वाले देशों के लिए घरेलू भोजन बर्बादी के प्रति व्यक्ति औसत स्तर में केवल 7 किलोग्राम का अंतर देखा गया है।
- खाद्य अपशिष्ट और जलवायु परिवर्तन के बीच संबंध का विवरण देते हुए, रिपोर्ट में पाया गया कि भोजन की हानि और अपशिष्ट से "वार्षिक वैश्विक ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन का 8-10% है। इससे विमानन क्षेत्र का लगभग 5 गुना और दुनिया की लगभग एक तिहाई कृषि भूमि के बराबर महत्वपूर्ण जैव विविधता का नुकसान होता है।"
- इसके आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्रों की तुलना में, ग्रामीण इलाकों में आम तौर पर कम भोजन बर्बाद होता है, जिसका कारण "पालतू जानवरों, पशुधन और घरेलू खाद बनाने के लिए भोजन के बचे हुए हिस्से का अधिक उपयोग" होता है।

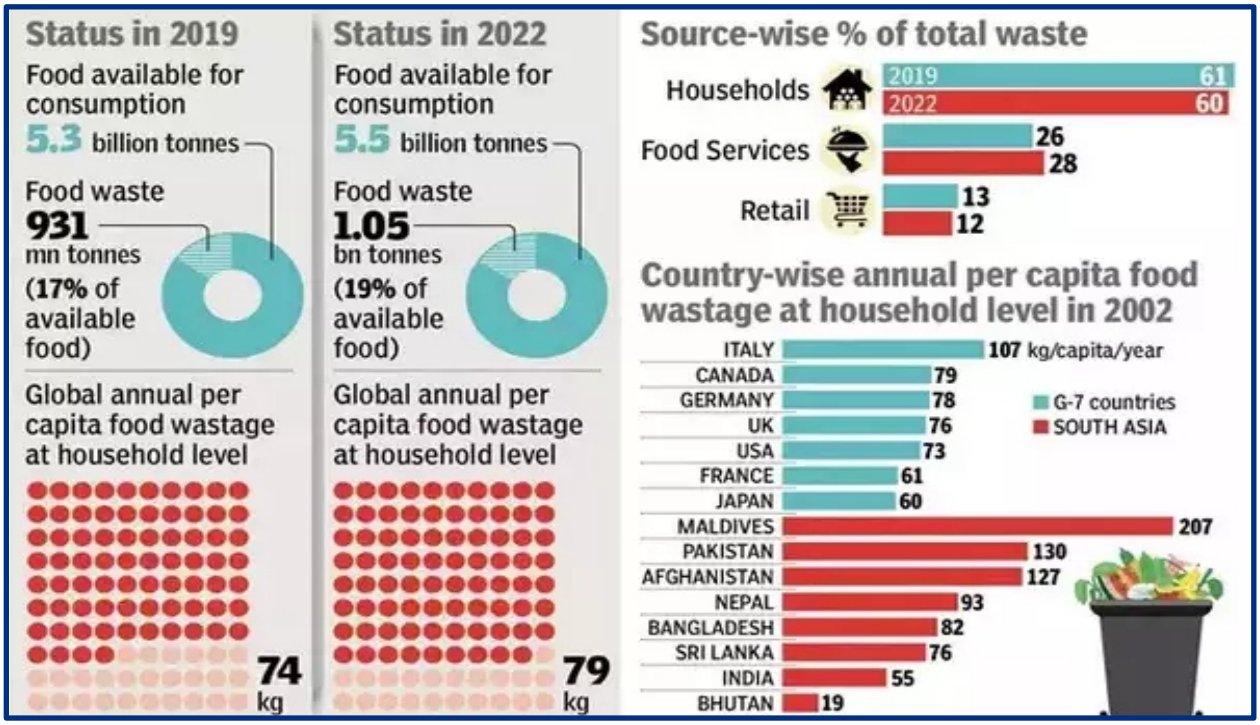

भारत - ईएफटीए व्यापार एवं आर्थिक साझीदारी समझौता

सुर्खियों में क्यों?

- 10 मार्च 2024 को भारत-यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन (ईएफटीए) ने एक व्यापार एवं आर्थिक साझीदारी समझौता (टीईपीए) पर हस्ताक्षर किए।

समझौते की मुख्य विशेषताएं:

- ईएफटीए ने अगले 15 वर्षों में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के स्टॉक को 100 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने और ऐसे निवेशों के माध्यम से भारत में 1 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार के सृजन की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता जताई है।
- एफटीए के इतिहास में पहली बार लक्ष्य-उन्मुख निवेश को बढ़ावा देने और रोजगारों के सृजन के बारे में कानूनी प्रतिबद्धता जताई जा रही है।
- ईएफटीए अपनी 92.2 प्रतिशत टैरिफ लाइनों की पेशकश कर रहा है जो भारत के 99.6 प्रतिशत निर्यात को कवर करता है। ईएफटीए के बाजार पहुंच प्रस्ताव में 100 प्रतिशत गैर-कृषि उत्पाद और प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद (पीएपी) पर टैरिफ रियायत शामिल है।

- टीईपीए हमारी प्रमुख ताकत/रुचि के क्षेत्रों जैसे आईटी सेवाओं, व्यावसायिक सेवाओं, व्यक्तिगत, सांस्कृतिक, खेल और मनोरंजक सेवाओं, अन्य शिक्षा सेवाओं, ऑडियो- विजुअल सेवाओं आदि में हमारी सेवाओं के निर्यात को प्रोत्साहित करेगा।
- ईएफटीए की सेवाओं की पेशकश में सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी, वाणिज्यिक उपस्थिति और प्रमुख कर्मियों के प्रवेश और अस्थायी प्रवास के लिए बेहतर प्रतिबद्धताओं और निश्चितता के माध्यम से बेहतर पहुंच शामिल है।
- टीईपीए में नर्सिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट आदि जैसी व्यावसायिक सेवाओं में पारस्परिक मान्यता समझौतों के प्रावधान हैं।
- टीईपीए में बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित प्रतिबद्धताएं ट्रिप्स स्तर पर हैं। स्विट्जरलैंड के साथ आईपीआर अध्याय, जहां आईपीआर के लिए उच्च मानक हैं, हमारी मजबूत आईपीआर व्यवस्था को दर्शाता है। जेनेरिक दवाओं में भारत के हितों और पेटेंट की सदाबहारता (एवरग्रीनिंग) यानी सदाबहार की प्रक्रिया में शामिल पेटेंट कानून और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून के विशिष्ट पहलू, से संबंधित चिंताओं को पूरी तरह से संबोधित किया गया है।
- भारत सतत विकास, समावेशी विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का संकेत देता है | व्यापार प्रक्रियाओं की पारदर्शिता, दक्षता, सरलीकरण, सामंजस्य और स्थिरता को बढ़ावा देता है
- टीईपीए हमारे निर्यातकों को विशेष इनपुट तक पहुंच को सशक्त बनाएगा और अनुकूल व्यापार और निवेश माहौल तैयार करेगा। इससे भारत में निर्मित वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही सेवा क्षेत्र को अधिक बाजारों तक पहुंचने के अवसर मिलेंगे।
- टीईपीए यूरोपीय संघ के बाजारों में एकीकृत होने का अवसर प्रदान करता है। स्विट्ज़रलैंड का 40 प्रतिशत से अधिक वैश्विक सेवा निर्यात यूरोपीय संघ को होता है। भारतीय कंपनियां यूरोपीय संघ तक अपनी बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए स्विट्जरलैंड को आधार के रूप में देख सकती हैं।
- टीईपीए बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी, विनिर्माण, मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, खाद्य प्रसंस्करण, परिवहन और लॉजिस्ट्क्सि, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं और बीमा जैसे क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करके "मेक इन इंडिया" और आत्मनिर्भर भारत को गति देगा।
- टीईपीए भारत में अगले 15 वर्षों में व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण के लिए बेहतर सुविधाओं सहित भारत के युवा महत्वाकांक्षी कार्यबल के लिए बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष रोजगारों के सृजन में तेजी लाएगा। टीईपीए सटीक इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य विज्ञान, नवीकरणीय ऊर्जा, नवोन्मेषण और अनुसंधान एवं विकास में प्रौद्योगिकी सहयोग और विश्व की अग्रणी प्रौद्योगिकियों तक पहुंच की सुविधा भी प्रदान करता है।

EFTA क्या है?

- EFTA एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसे वर्ष 1960 में उन यूरोपीय राज्यों के लिये एक वैकल्पिक व्यापार ब्लॉक के रूप में स्थापित किया गया था जो यूरोपीय संघ (EU) में शामिल होने में असमर्थ या अनिच्छुक थे।
- EFTA में आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड शामिल हैं,

जो यूरोपीय संघ के अंग नहीं हैं, लेकिन विभिन्न समझौतों के माध्यम से इसके एकल बाज़ार तक पहुँच रखते हैं।

- ईएफटीए भारत का 9 वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जिसका 2020-21 में भारत के कुल व्यापारिक व्यापार का लगभग 2.5% हिस्सा है।
- ईएफटीए को भारत के निर्यात की मुख्य वस्तुएं कपड़ा, रसायन, रत्न और आभूषण, मशीनरी और फार्मास्यूटिकल्स हैं।
- ईएफटीए से भारत के आयात की मुख्य वस्तुएं मशीनरी, रसायन, कीमती धातुएं और चिकित्सा उपकरण हैं।

भारत-मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत-मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को सशक्त बनाने तथा संचालन के लिए सहयोग से संबंधित भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अंतर-सरकारी फ्रेमवर्क समझौते को मंजूरी दी गई।
- इस अंतर-सरकारी फ्रेमवर्क समझौते का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाना एवं बंदरगाहों, समुद्री तथा लॉजिस्टिक क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत बनाना है।
- इस समझौते में दोनों देशों के बीच सहयोग की विस्तृत रूपरेखा है। यह सहयोग पारस्परिक रूप से सहमत सिद्धांतों, दिशानिर्देशों और दोनों देश के अधिकार क्षेत्रों के तहत प्रासंगिक नियमों एवं विनियमों के अनुरूप समझौतों के एक समुच्चय पर आधारित होगा।

भारत -मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) क्या है?

- भारत -मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) एक नियोजित आर्थिक गलियारा है जिसका उद्देश्य एशिया , फारस की खाड़ी और यूरोप के बीच कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है ।
- यह गलियारा भारत से संयुक्त अरब अमीरात , सऊदी अरब , जॉर्डन , इज़राइल और ग्रीस के माध्यम से यूरोप तक प्रस्तावित है ।

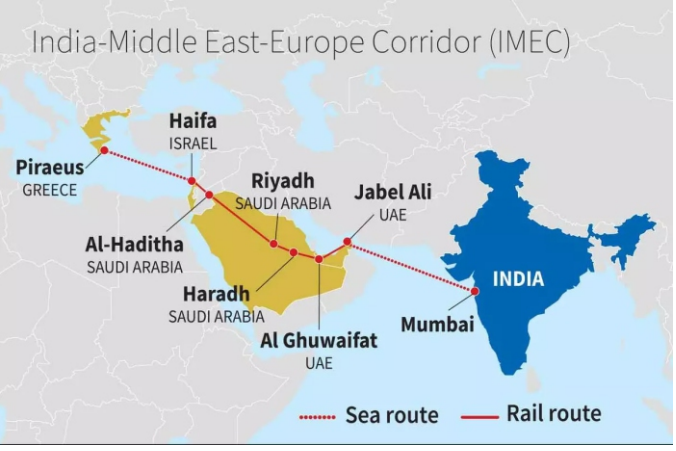

- गौरतलब है कि 10 सितंबर 2023 को भारत , संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, फ्रांस , जर्मनी , इटली और यूरोपीय संघ की सरकारों द्वारा नई दिल्ली में आयोजित जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये गए थे।
- इसका उद्देश्य भारत, मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ने वाला एक व्यापक परिवहन नेटवर्क बनाना है, जिसमें रेल, सड़क तथा समुद्री मार्ग शामिल हैं। गलियारे में एक विद्युत केबल, एक हाइड्रोजन पाइपलाइन और एक हाई-स्पीड डेटा केबल भी शामिल होंगे।
- इससे व्यापार और कनेक्टिविटी को सुविधाजनक बनाकर एशिया, यूरोप तथा मध्य पूर्व के एकीकरण में बदलाव आने की आशा है।
- यह परियोजना रेल और शिपिंग नेटवर्क के माध्यम से यूरोप और एशिया के बीच परिवहन और संचार लिंक को मजबूत करने के लिए शुरू की गई थी और इसे चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के जवाब के रूप में देखा जाता है ।

भारत-प्रशांत आर्थिक ढांचा (IPEF) की मंत्रिस्तरीय बैठक

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल अमेरिकी वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो, थाई उपप्रधान मंत्री और विदेश मंत्री पारनप्री बहिधा-नुकारा के साथ भारत-प्रशांत आर्थिक ढांचा (आईपीईएफ) के साझेदार मंत्रियों के साथ वर्चुअल मंत्रिस्तरीय बैठक में शामिल हुए।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान, आईपीईएफ भागीदारों ने नवंबर 2023 में हुई बैठक में प्रस्तावित आईपीईएफ स्वच्छ अर्थव्यवस्था समझौते और आईपीईएफ निष्पक्ष अर्थव्यवस्था समझौते का स्वागत किया। इसके अतिरिक्त, भारत-प्रशांत आर्थिक ढांचा के साझेदारों ने 24 फरवरी 2024 से आईपीईएफ आपूर्ति श्रृंखला समझौते के लागू होने का स्वागत किया।
- आईपीईएफ भागीदारों ने अगले कई महीनों में फ्रेमवर्क के अंतर्गत ठोस परिणाम देने के लिए अगले कदमों पर भी चर्चा की। इसमें स्वच्छ अर्थव्यवस्था स्तंभ के अंतर्गत प्रयास की कई नई लाइनें शामिल हैं, जिसमें चार नए सहकारी कार्य कार्यक्रमों (सीडब्ल्यूपी) का शुभारंभ की घोषणा की गई ।
- कार्बन बाजारों पर, इच्छुक आईपीईएफ साझेदार शुरू में मौजूदा क्षेत्रीय कार्बन बाजार की प्राथमिकताओं को समझने और सहयोग के लिए सक्षम स्थितियों में सुधार के लिए रणनीतियों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं;
- इच्छुक आईपीईएफ साझेदार सार्वजनिक-निजी सहयोग सहित इस क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच बढ़ाने और डीकार्बोनाइजेशन को सुविधाजनक बनाने के लिए स्वच्छ बिजली वृद्धि पर भी काम कर रहे हैं;
- रोजगार सृजन और श्रम अधिकारों को बढ़ावा देने तथा स्वच्छ ऊर्जा की

दिशा में रोजगार बदलाव को संबोधित करने के प्रयासों को मजबूत करने के लिए, इच्छुक आईपीईएफ भागीदार स्वच्छ अर्थव्यवस्था प्राप्त करने की दिशा में उचित परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए कार्यबल विकास प्रयासों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं;

- इच्छुक आईपीईएफ भागीदार टिकाऊ विमानन ईंधन (एसएएफ) और उसके कच्चे माल (फीडस्टॉक्स) की उपलब्धता और सामर्थ्य बढ़ाने के लिए टिकाऊ विमानन ईंधन (सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल - एसएएफ) पर सहयोग करेंगे, ताकि इस क्षेत्र में क्षेत्रीय एसएएफ मूल्य श्रृंखलाओं को उत्प्रेरित और विकसित किया जा सके।
- ध्यान रहे, आपूर्ति श्रृंखला समझौते, स्वच्छ अर्थव्यवस्था समझौते, निष्पक्ष अर्थव्यवस्था समझौते और आईपीईएफ पर समझौते के लिए चर्चा करने के उद्देश्य से सभी मंत्री 06 जून 2024 को सिंगापुर में व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे।
- आईपीईएफ स्वच्छ अर्थव्यवस्था समझौता स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में तेजी लाने, ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु लचीलापन और अनुकूलन बढ़ाने तथा आईपीईएफ सदस्य देशों में स्थायी आजीविका का समर्थन करने के लिए आईपीईएफ भागीदारों के बीच उनके संबंधित प्रयासों में सहयोग बढ़ाने की सुविधा प्रदान करता है।
- इस समझौते के कार्यान्वयन पर, स्वच्छ अर्थव्यवस्था क्षेत्र में भारत में आवक निवेश बढ़ने, कम लागत वाली जलवायु प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा मिलने, तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण की सुविधा के साथ ही भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर प्रदान करने और अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है।

भारत-प्रशांत आर्थिक ढांचा (आईपीईएफ) के बारे में

- भारत-प्रशांत आर्थिक ढांचे (Indo-Pacific Economic Framework-IPEF) को मई 2022 में शुरू किया गया था, जिसमें 14 क्षेत्रीय साझेदारों - ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम को आर्थिक सहयोग के एक नए के अंतर्गत मॉडल एक साथ लाया गया था।
- आईपीईएफ वार्ता 2022 के अंत में शुरू हुई। मई 2023 में, आईपीईएफ भागीदारों ने अपनी तरह के पहले आईपीईएफ आपूर्ति श्रृंखला समझौते के लिए वार्ता के पर्याप्त निष्कर्ष की घोषणा की।
- नवंबर 2023 में, आईपीईएफ के भागीदारों ने प्रस्तावित आईपीईएफ स्वच्छ अर्थव्यवस्था और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था समझौतों के साथ-साथ ढांचे के स्थायित्व को सुनिश्चित करने में सहायता करने के लिए आईपीईएफ पर एक प्रस्तावित व्यापक समझौते पर वार्ता के पर्याप्त निष्कर्ष की घोषणा की और आईपीईएफ आपूर्ति श्रृंखला समझौते के लिए एक हस्ताक्षर समारोह का आयोजन किया।

ऑपरेशन इंद्रावती

सुर्खियों में क्यों?

- हैती की राजधानी पोर्ट-ऑ-प्रिंस में सशस्त्र गिरोहों द्वारा किए जा रहे नए हमलों की पृष्ठभूमि में, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 21 मार्च 2024 को हैती से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए "ऑपरेशन इंद्रावती" शुरू किया।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- यह विकास ऐसे समय में हुआ है जब देश, जो अभी भी 2010 के भूकंप से उबर नहीं पाया है, हिंसक गिरोह युद्ध देख रहा है।
- 29 फरवरी को, हैती के गिरोहों ने पोर्ट-ऑ-प्रिंस में हमले किए। अगले कुछ दिनों में, उन्होंने पुलिस स्टेशनों को जला दिया, देश के मुख्य हवाई अड्डे को बंद कर दिया, दो सबसे बड़ी जेलों पर हमला किया और हजारों कैदियों को मुक्त करा लिया।
- 3 मार्च को, हैती ने आपातकाल की घोषणा की और रात का कर्फ्यू लगा दिया।
- हैती के सबसे शक्तिशाली गैंग लीडर जिमी चेरिज़ियर देश के कार्यवाहक प्रधान मंत्री एरियल हेनरी के इस्तीफे की मांग कर रहे थे।

हैती के बारे में

- हैती, कैरेबियन सागर में एक देश जिसमें हिस्पानियोला द्वीप का पश्चिमी भाग और गोनवे, टोर्ट्यू (टोर्टुगा), ग्रांडे के और वाचे जैसे छोटे द्वीप शामिल हैं। इसकी राजधानी पोर्ट-ऑ-प्रिंस है।
- हैती, जिसकी आबादी लगभग पूरी तरह से गुलाम अफ्रीकी लोगों की वंशज है, ने 1804 में फ्रांस से स्वतंत्रता हासिल की, जिससे यह संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद औपनिवेशिक शासन से मुक्त होने वाला अमेरिका का दूसरा देश बन गया।
- हालाँकि, सदियों से, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कठिनाइयों के साथ-साथ कई प्राकृतिक आपदाओं ने हैती को पुरानी गरीबी और अन्य गंभीर समस्याओं से घेर लिया है।

डीआरडीओ का 'मिशन दिव्यास्त्र'

सुर्खियों में क्यों?

- 11 मार्च 2024 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल (MIRV) प्रौद्योगिकी से लैस स्वदेश में विकसित अग्नि-5 मिसाइल का प्रथम सफल उड़ान परीक्षण किया।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- 'मिशन दिव्यास्त्र 'नामक यह उड़ान परीक्षण ओडिशा के डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया।
- मिशन दिव्यास्त्र एक ऐसा मिशन है जिसमें एक ही मिसाइल को विभिन्न युद्ध स्थलों पर निशाना बनाकर तैनात किया जा सकता है । यह प्रणाली स्वदेशी एवियोनिक्स प्रणालियों और उच्च सटीकता सेंसर पैकेजों से लैस है ।
- मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल (MIRV) तकनीक उस तकनीक को कहते है जिसमें किसी मिसाइल में एक ही बार में कई परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता होती है। इन हथियारों से दुश्मन के अलग-अलग लक्ष्यों को भेदा जा सकता है।

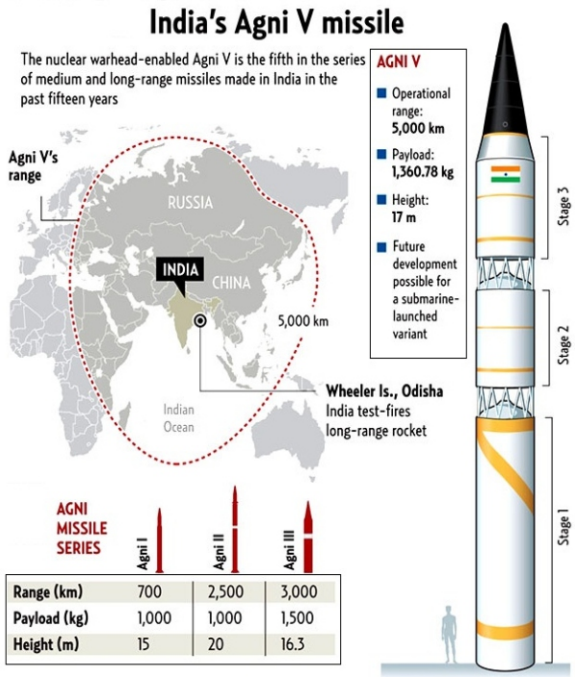

अग्नि 5 मिसाइल के बारे में

- अग्नि 5 मिसाइल एक अंतर-महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (Inter-Continental Ballistic Missile- ICBM) है जो अग्नि सीरीज की 5000 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता वाली सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है।
- भारत ने दिसंबर 2022 में परमाणु क्षमता से लैस अग्नि-5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था।
- अग्नि-5 एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (Integrated Guided Missile Development Programme- IGMDP) के तहत विकसित सतह-से-सतह पर मार करने वाली उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल है।
- यह दागो और भूल जाओ मिसाइल है, जिसे इंटरसेप्टर मिसाइल के बिना रोका नहीं जा सकता है।
- अग्नि-1 से 5 मिसाइलें रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा डिज़ाइन और विकसित की गई हैं।

भारत सेमीकंडक्टर मिशन

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'भारत में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास' के अंतर्गत तीन सेमीकंडक्टर इकाइयां लगाने को मंजूरी प्रदान की है।
- अगले 100 दिन के भीतर तीनों इकाइयों का निर्माण शुरू हो जाएगा।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून, 2023 में गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर इकाई लगाने के लिए माइक्रोन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की थी।

स्वीकृत की गई तीन सेमीकंडक्टर इकाइयां हैं:

- 50,000 wfsm (wafer starts per month) क्षमता के साथ सेमीकंडक्टर फैब : टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ("TEPL") पावरचिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प (PSMC), ताइवान के साथ साझेदारी में एक सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करेगी। इस फैब का निर्माण गुजरात के धोलेरा में किया जाएगा। इस फैब में 91,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।
- असम में सेमीकंडक्टर एटीएमपी इकाई: टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड ("टीएसएटी") असम के मोरीगांव में एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करेगी। टीएसएटी सेमीकंडक्टर फ्लिप चिप और आईएसआईपी (पैकेज में एकीकृत प्रणाली) प्रौद्योगिकियों सहित स्वदेशी उन्नत सेमीकंडक्टर पैकेजिंग प्रौद्योगिकियों का विकास कर रहा है।

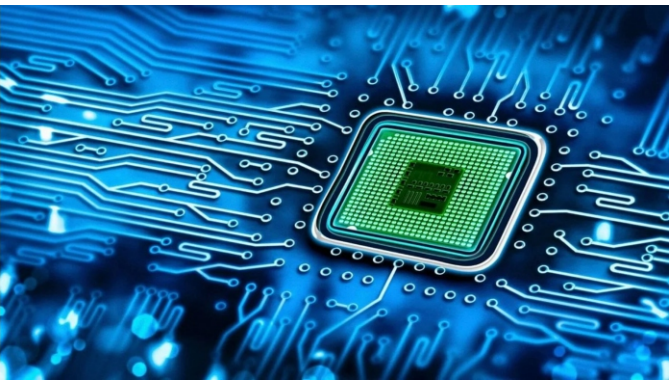

- विशेष चिप्स के लिए सेमीकंडक्टर एटीएमपी इकाई : सीजी पावर, रेनेसा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, जापान और स्टार्स माइक्रो-इलेक्ट्रॉनिक्स, थाईलैंड के साथ साझेदारी में गुजरात के साणंद में एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करेगी। रेनेसा एक अग्रणी सेमीकंडक्टर कंपनी है जो विशेष चिप्स पर केंद्रित है।

इन इकाइयों का सामरिक महत्व :

- इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ने बहुत ही कम समय में चार बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। इन इकाइयों से भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम स्थापित हो जायेगा।
- भारत के पास पहले से ही चिप डिजाइन में गहन क्षमताएं मौजूद हैं। इन इकाइयों के साथ, हमारा देश चिप विनिर्माण (या चिप फेब्रिकेशन) में क्षमता विकसित कर लेगा।
- इसकी घोषणा के साथ ही भारत में उन्नत पैकेजिंग प्रौद्योगिकियों को स्वदेशी रूप से विकसित किया जाएगा।
- ये इकाइयां 20 हजार उन्नत प्रौद्योगिकी कार्यों में प्रत्यक्ष रोजगार और लगभग 60 हजार अप्रत्यक्ष रोजगारों का सृजन करेंगी।
- ये इकाइयां डाउनस्ट्रीम ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, दूरसंचार विनिर्माण, औद्योगिक विनिर्माण और अन्य सेमीकंडक्टर उपभोक्ता उद्योगों में रोजगार सृजन में तेजी लाएंगी।

इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में

- ISM को वर्ष 2021 में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तत्त्वावधान में कुल 76,000 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ लॉन्च किया गया था।
- यह देश में स्थायी अर्द्धचालक और प्रदर्शन पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिये व्यापक कार्यक्रम का हिस्सा है।
- कार्यक्रम का उद्देश्य अर्द्धचालक, डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइन इकोसिस्टम में निवेश करने वाली कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- अर्द्धचालक और डिस्प्ले उद्योग में वैश्विक विशेषज्ञों के नेतृत्व में आईएसएम योजनाओं के कुशल, सुसंगत एवं सुचारू कार्यान्वयन के लिये नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।

इंडिया AI मिशन

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने "मेकिंग एआई इन इंडिया" और "मेकिंग एआई वर्क इन इंडिया" के विज़न पर चलते हुए 10,371.92 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ राष्ट्रीय स्तर के बेहद व्यापक इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दे दी है।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- ये इंडिया एआई मिशन, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में रणनीतिक कार्यक्रमों और साझेदारी के जरिए एआई नवाचार को उत्प्रेरित करने वाला एक बड़ा इकोसिस्टम स्थापित करेगा।
- इस पहल से कंप्यूटिंग तक पहुंच के लोकतंत्रीकरण, डेटा गुणवत्ता में सुधार, स्वदेशी एआई क्षमताओं के विकास, टॉप एआई टैलेंट को लुभाने, इंडस्ट्री के सहयोग को सक्षम करने, स्टार्टअप जोखिम पूंजी प्रदान करने, सामाजिक रूप से प्रभावशाली एआई परियोजनाओं को सुनिश्चित करने और नैतिक एआई को मजबूत करने से भारत के एआई इकोसिस्टम के जिम्मेदार, समावेशी विकास को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

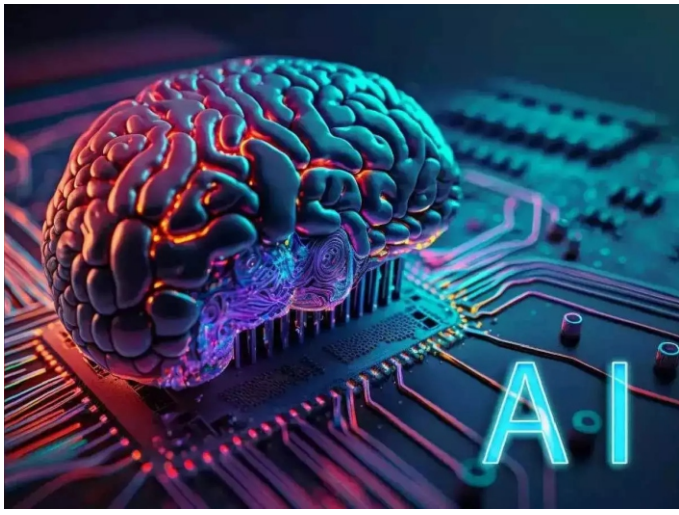

- इंडिया एआई मिशन भारत की तकनीकी संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए नवाचार को बढ़ावा देगा और घरेलू क्षमताओं का निर्माण करेगा। ये देश के जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग करने के लिए बेहद कुशल रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा।
- इस मिशन को डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन (डीआईसी) के अंतर्गत 'इंडिया एआई' इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन (आईबीडी) द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा और इसमें निम्नलिखित घटक होंगे :
  1. इंडिया एआई कंप्यूट क्षमता - इंडिया एआई का ये कंप्यूटिंग वाला स्तंभ भारत के तेजी से बढ़ते एआई स्टार्ट-अप और रिसर्च इकोसिस्टम की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए एक उच्च-

स्तरीय विस्तार योग्य एआई कंप्यूटिंग इकोसिस्टम का निर्माण करेगा। इस इकोसिस्टम में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के जरिए निर्मित 10,000 या उससे ज्यादा ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (जीपीयू) का एआई कंप्यूट बुनियादी ढांचा शामिल होगा। इसके अलावा, एक एआई बाजार डिजाइन किया जाएगा जो एआई इनोवेटर्स को एक सेवा और पूर्व-प्रशिक्षित मॉडलों के रूप में एआई की पेशकश करेगा। ये एआई नवाचार के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों का एकल बिंदु समाधान भी होगा।

2. इंडिया एआई नवाचार केंद्र - इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्वदेश में निर्मित बड़े मल्टीमोडल मॉडलों (एलएमएम) और डोमेन-विशिष्ट बुनियादी मॉडल के विकास और तैनाती का काम करेगा।
3. इंडिया एआई डेटासेट मंच - इंडिया एआई डेटासेट मंच एआई नवाचार के लिए गुणवत्ता वाले गैर-व्यक्तिगत डेटासेट तक पहुंच को सुगम करेगा। भारतीय स्टार्टअपों और शोधकर्ताओं की गैर-व्यक्तिगत डेटासेट तक बेरोक पहुंच के लिए वन-स्टॉप समाधान प्रदान करने के लिए एक एकीकृत डेटा प्लेटफ़ॉर्म विकसित किया जाएगा।
4. इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव - इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट की पहल केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य विभागों और अन्य संस्थानों से प्राप्त समस्याओं के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एआई के इस्तेमाल को बढ़ावा देगा। ये पहल बड़े पैमाने पर सामाजिक-आर्थिक बदलाव को उत्प्रेरित करने की क्षमता वाले प्रभावशाली एआई समाधानों को विकसित करने/बढ़ाने/अपनाने को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगी।
5. इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स - इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स की कल्पना एआई प्रोग्रामों में प्रवेश संबंधी बाधाओं को कम करने के लिए की गई है। ये स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर और पीएचडी की पढ़ाई में एआई पाठ्यक्रमों को बढ़ाएगी। इसके अलावा, बुनियादी स्तर के पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए पूरे भारत के टियर 2 और टियर 3 शहरों में डेटा और एआई लैब्स स्थापित की जाएंगी।
6. इंडिया एआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग - इंडिया एआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग के स्तंभ की परिकल्पना डीप-टेक एआई स्टार्टअप को समर्थन और गति देने और उन्हें भविष्य की एआई परियोजनाओं के लिए फंडिंग तक सुगम पहुंच प्रदान करने के लिए की गई है।
7. सुरक्षित और भरोसेमंद एआई - एआई के जिम्मेदारी भरे विकास, तैनाती और उसे अपनाए जाने के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सजगता की जरूरत को पहचानते हुए, सुरक्षित और भरोसेमंद एआई का ये स्तंभ जिम्मेदारी भरी एआई परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सक्षम करेगा जिनमें स्वदेशी उपकरणों और ढांचे का विकास, नवप्रवर्तकों के लिए आत्म-मूल्यांकन के बिंदु, अन्य दिशानिर्देश और गवर्नेंस फ्रेमवर्क शामिल हैं।

स्केलेबल इंस्ट्रक्शनल मल्टीवर्ल्ड एजेंट (SIMA)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में एक नई तकनीकी रिपोर्ट में, Googles के डीपमाइंड ने SIMA (Scalable Instructable Multiworld Agent) पेश किया है, जो 3D वर्चुअल सेटिंग्स के लिए एक सामान्य एआई एजेंट है। यह एक सामान्य व्यक्तिगत गेम को, निर्देश योग्य गेम-प्लेइंग एआई एजेंट की ओर स्थानांतरित करने पर फोकस करता है।

SIMA से संबंधित प्रमुख बिंदु

- SIMA एक स्केलेबल इंस्ट्रक्शनल मल्टीवर्ल्ड एजेंट है जो विभिन्न वीडियो गेम सेटिंग में कार्यों को पूरा करने के लिए प्राकृतिक भाषा के निर्देशों का पालन कर सकता है।
- SIMA गेमिंग के भविष्य की ओर इशारा करता है जहां AI एजेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यह हमें एआई के एक कदम और करीब ले जाता है जो न केवल खेलों में बल्कि वास्तविक दुनिया के वातावरण में कार्य करने में भी मनुष्यों के साथ बुद्धिमानी से सहयोग कर सकता है।
- यह एक आभासी दोस्त की तरह है जो सभी प्रकार के आभासी वातावरणों में निर्देशों को समझ सकता है और उनका पालन कर सकता है - रहस्यमय कालकोठरी की खोज से लेकर भव्य महल बनाने तक।
- यह अनिवार्य रूप से एक सुपर-स्मार्ट कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे एक डिजिटल एक्सप्लोरर के रूप में सोचा जा सकता है, जिसमें यह समझने की क्षमता है कि आप क्या चाहते हैं और आभासी दुनिया में इसे बनाने में मदद करते हैं।

- इस एआई एजेंट की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि यह सीखने और अनुकूलन करने में सक्षम है। SIMA उपयोगकर्ता के साथ अपनी बातचीत के माध्यम से ऐसा करता है।
- इसमें सटीक छवि-भाषा मैपिंग के लिए डिज़ाइन किया गया एक मॉडल और एक वीडियो मॉडल शामिल है जो भविष्यवाणी करता है कि स्क्रीन पर आगे क्या होगा।

PSLV कक्षीय प्रायोगिक मॉड्यूल 3 (POEM 3) मिशन

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने घोषणा की कि उसका पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल-3 (पीओईएम-3) कक्षा में कोई मलबा छोड़े बिना पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश कर गया।

POEM-3 के बारे में

- POEM-3 को नव विकसित स्वदेशी प्रणालियों पर प्रौद्योगिकी प्रदर्शन और वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए कुल 9 विभिन्न प्रयोगात्मक पेलोड के साथ कॉन्फ़िगर किया गया था।
- इनमें से छह पेलोड एनजीई द्वारा IN-SPACe के माध्यम से वितरित किए गए थे। इन पेलोड के मिशन उद्देश्य एक महीने में पूरे हो गए।
- विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी) ने पीएसएलवी के चौथे चरण को बढ़ाकर पीओईएम की अवधारणा और कार्यान्वयन में अग्रणी भूमिका निभाई है।
- ऊपरी चरण की कक्षीय ऊंचाई प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव में घटती रही, मुख्य रूप से वायुमंडलीय खिंचाव के साथ मॉड्यूल के 21 मार्च, 2024 को उत्तरी प्रशांत महासागर पर प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।
- पीओईएम के माध्यम से, जो छोटी अवधि के अंतरिक्ष-जनित प्रयोगों को करने के लिए एक बहुत ही लागत प्रभावी मंच के रूप में कार्य करता है, इसरो ने अपने नए पेलोड के साथ प्रयोग करने के लिए शिक्षाविदों, स्टार्टअप और एनजीई के लिए नए रास्ते खोले हैं।
- इस नवीन अवसर का उपयोग अंतरिक्ष में प्रयोग करने के लिए कई स्टार्टअप, विश्वविद्यालयों और एनजीई द्वारा प्रभावी ढंग से किया गया है, जिसमें इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स, सैटेलाइट डिस्पेंसर और स्टार-ट्रैकिंग शामिल हैं।
- POEM में एकल-श्रृंखला कॉन्फ़िगरेशन में कुल एवियोनिक्स, मिशन प्रबंधन कंप्यूटर सहित एवियोनिक्स पैकेज में औद्योगिक-ग्रेड घटक, इलेक्ट्रिक पावर, टेलीमेट्री और टेलीकॉम के लिए मानक इंटरफेस और दर-जाइरो, सन सेंसर और मैग्नेटोमीटर का उपयोग करने वाले नए इन-ऑर्बिट नेविगेशन एल्गोरिदम जैसी नई सुविधाएं भी शामिल हैं।
- इसरो ने लागत-कुशल कक्षीय प्रयोग मंच की पेशकश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। अंतरिक्ष मलबे से उत्पन्न बढ़ते खतरे को पहचानते हुए, विशेष रूप से कई छोटे उपग्रह समूहों के उद्भव के साथ, एजेंसी ने उपग्रह प्रक्षेपण, मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रयासों और अन्वेषण मिशनों सहित अंतरिक्ष संचालन के लिए महत्वपूर्ण खतरे पर जोर दिया।

एम्युनिशन- कम -टॉरपीडो-कम-मिसाइल (ACTCM) बार्ज प्रोजेक्ट

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारतीय नौसेना के लिए एमएसएमई शिपयार्ड, मेसर्स सूर्यदिप्ता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ठाणे द्वारा निर्मित 11 एक्स एसीटीसीएम बार्ज प्रोजेक्ट के 5वें बार्ज 'एम्युनिशन कम टॉरपीडो कम मिसाइल बार्ज - LSAM 19 ' की डिलीवरी 04 मार्च 2024 को एनएडी (करंजा) के लिए नौसेना डॉकयार्ड, मुंबई में की गई।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि 11 एक्स एसीटीसीएम बार्ज के निर्माण के लिए 05 मार्च 2021 को रक्षा मंत्रालय और मेसर्स सूर्यदीप्त प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ठाणे के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- इन बार्जों को भारतीय नौसेना के प्रासंगिक नियमों और भारतीय शिपिंग रजिस्टर के विनियमन के अंतर्गत स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया हैं।
- डिजाइन चरण के दौरान बार्ज के मॉडल का परीक्षण नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला, विशाखापत्तनम में किया गया था। ये बार्ज भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के गौरवशाली ध्वजवाहक हैं।
- इन बार्जों के शामिल होने से सामाग्री/गोला-बारूद के परिवहन, उतारने-चढ़ाने की सुविधा के माध्यम से जेटी के किनारे और बाहरी बंदरगाह दोनों पर भारतीय नौसेना के जहाजों की परिचालन प्रतिबद्धताओं को गति मिलेगी।

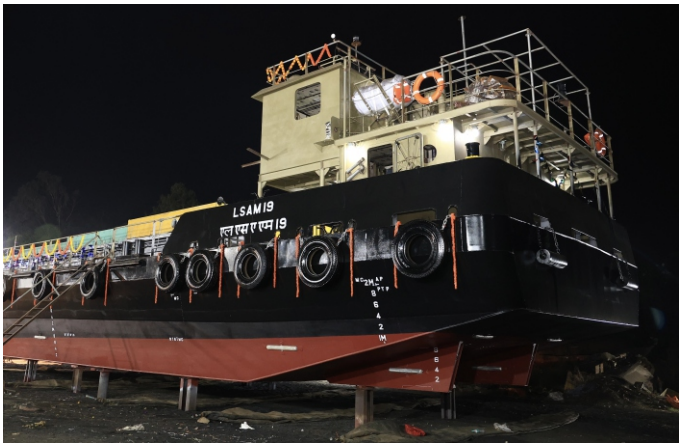

भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव ने नई दिल्ली में भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की।
- इस अवसर पर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) और भारतीय वन्यजीव संस्थान के सहयोग से भारत में तेंदुए की आबादी के आकलन के पांचवें चक्र का अनावरण किया गया। यह रिपोर्ट बढ़ते खतरों के बीच विभिन्न परिदृश्यों में तेंदुओं की आबादी की स्थिति और रुझान पर प्रकाश डालती है।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- भारत में तेंदुओं की आबादी 13,874 अनुमानित है, जो पिछले अनुमान की तुलना में स्थिरता दर्शाती है। हालाँकि, यह तेंदुए के निवास का केवल 70% प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें हिमालय और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों का नमूना नहीं लिया गया है।
- मध्य भारत में स्थिर या थोड़ी बढ़ती जनसंख्या प्रदर्शित हो रही है, जबकि शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के मैदानों में गिरावट का अनुभव हो रहा है। चयनित क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग रुझानों के साथ, प्रति वर्ष 1.08% की वृद्धि दर है।
- देश में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या मध्यप्रदेश (3907) में है। इसके बाद महाराष्ट्र (1985), कर्नाटक (1,879) और तमिलनाडु (1,070) हैं। टाइगर रिजर्व या सबसे अधिक तेंदुए की आबादी वाले स्थल- आंध्रप्रदेश के श्रीशैलम में नागार्जुन सागर और इसके बाद मध्यप्रदेश में पन्ना और सतपुड़ा हैं। वर्ष 2018 में तेंदुओं की संख्या मध्यप्रदेश में 3421, महाराष्ट्र में 1690, कर्नाटक में 1783 और तमिलनाडु में 868 था।

तेंदुआ (Leopard) के बारे में

- तेंदुआ पकड़ में न आने वाला और रात्रि में विचरण करने वाला जानवर है जिसका आकार तथा रंग उसके निवास स्थान पर निर्भर करता है।
- इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा पार्डस है जो बिल्ली परिवार के सदस्य है।
- तेंदुए एशिया, उप-सहारा अफ्रीका, दक्षिणी रूस और भारतीय उप-महाद्वीप में पाए जाते हैं। भारतीय तेंदुआ (पैंथेरा पर्डस फुस्का) भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापक रूप से पाया जानेवाला एक तेंदुआ है।
- प्राकृतिक निवास स्थान का नुकसान, अवैध शिकार एवं मानव-वन्यजीव संघर्ष तेंदुओं की आबादी के लिए खतरा के रूप में चिन्हित किया गया है।
- यह IUCN की रेड लिस्ट में असुरक्षित/लुप्तप्राय प्राणी के रूप में तथा CITES के परिशिष्ट I और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची I में शामिल है।

अगलेगा (Agalega) द्वीपसमूह

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मॉरीशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविंद जगन्नाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मॉरीशस के अगालेगा द्वीप में छह सामुदायिक विकास परियोजनाओं के साथ-साथ नई हवाई पट्टी और सेंट जेम्स जेट्टी का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया।
- इन परियोजनाओं का उद्घाटन भारत और मॉरीशस के बीच मजबूत और दशकों पुरानी विकास साझेदारी का प्रमाण है, जिससे मुख्य भूमि मॉरीशस और अगालेगा के बीच बेहतर कनेक्टिविटी की मांग पूरी होगी, समुद्री सुरक्षा मजबूत होगी और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

- गौरतलब है कि वर्ष 2015 में भारत ने अगलेगा द्वीप समूह के विकास के लिये मॉरीशस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये थे। इस परियोजना में सैन्य सहयोग, एक नया हवाई अड्डा, बंदरगाह, लाजिस्टिक और संचार सुविधाएँ तथा संभावित परियोजना से संबंधित कोई अन्य सुविधाएँ शामिल है।
- अगलेगा द्वीप दक्षिण-पश्चिमी हिंद महासागर में मॉरीशस से 1,122 किमी. उत्तर में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 27 वर्ग मील (70 वर्ग किमी.) है।

अगालेगा द्वीप समूह भारत के लिए सामरिक महत्व का क्यों है?

- यह द्वीप समूह दक्षिण-पश्चिम हिंद महासागर में भारत की उपस्थिति को मज़बूत करेगा तथा इस क्षेत्र में अपनी शक्ति प्रदर्शन की आकांक्षाओं को सुविधाजनक बनाएगा। गौरतलब है कि भारत दक्षिण-पश्चिम हिंद महासागर में और एक खुफिया पोस्ट के रूप में हवाई तथा सतही समुद्री गश्त दोनों की सुविधा के लिये नए आधार को आवश्यक मानता है।
- यह एक "केंद्रीय भौगोलिक बिंदु" के रूप में हिंद महासागर में वाणिज्य और कनेक्टिविटी के लिये महत्त्व रखता है।
- हिंद महासागर से भारत का 95% व्यापार होता है और कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 80% समुद्र द्वारा आयात किया जाता है। इसलिये हिंद महासागर में उपस्थिति भारत के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- चीन के 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' का मुकाबला करने के लिये भारत को हिंद महासागर के बड़े क्षेत्र में उपस्थिति दर्ज करना बेहद ज़रूरी हो गया है। चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भारत के लिए रणनीतिक हितों के लिये खतरा साबित हो सकता है।
- इन परियोजनाओं से बेहतर कनेक्टिविटी की जरूरत पूरी होगी साथ ही समुद्री सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (आईबीसीए) की स्थापना को मंजूरी दे दी है।

- एलाएंस का मुख्यालय भारत में होगा और इसे 2023-24 से 2027-28 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपये की एकमुश्त बजटीय सहायता मिलेगी।

IBCA से संबंधित प्रमुख बिंदु

- यह एक प्रस्तावित मेगा-वैश्विक गठबंधन है जो सात प्रमुख बड़ी बिल्लियों: चीता, जगुआर, प्यूमा, हिम तेंदुआ , तेंदुआ, शेर और बाघ की सुरक्षा और संरक्षण की दिशा में काम करेगा।
- गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने बाघों, बड़ी बिल्ली परिवार की अन्य प्रजातियों तथा इसकी अनेक लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण में भारत की अग्रणी भूमिका को महत्त्व देते हुए, वैश्विक बाघ दिवस, 2019 के अवसर पर अपने भाषण में एशिया में अवैध शिकार को रोकने के लिए वैश्विक नेताओं के एलाएंस का आह्वान किया था।
- उन्होंने 9 अप्रैल, 2023 को भारत के प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इसे दोहराया और औपचारिक रूप से एक इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस प्रारंभ करने की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य बड़ी बिल्लियों और उनके द्वारा फूलने-फलने वाले परिदृश्यों के भविष्य को सुरक्षित बनाना है।
- इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस की परिकल्पना 96 बिग कैट रेंज देशों, बिग कैट संरक्षण में रुचि रखने वाले गैर-रेंज देशों, संरक्षण भागीदारों तथा बिग कैट संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिक संगठनों के बहु-देशीय, बहु-एजेंसी एलायंस के रूप में की गई है।
- परिकल्पना में बड़ी बिल्लियों के कार्य में योगदान के इच्छुक व्यावसायिक समूहों और कॉर्पोरेट्स की व्यवस्था के साथ-साथ नेटवर्क स्थापित करने तथा फोकस रूप से तालमेल विकसित करने की व्यवस्था है, ताकि एक सामान्य मंच पर केंद्रीकृत भंडार लाया जा सके, इसे वित्तीय समर्थन प्राप्त हो, जिसका लाभ बड़ी बिल्ली की आबादी में गिरावट को रोकने और इस प्रवृत्ति को बदलने में संरक्षण एजेंडा को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है।
- आईबीसीए का लक्ष्य संरक्षण एजेंडे को आगे बढ़ाने में पारस्परिक लाभ के लिए देशों के बीच आपसी सहयोग करना है। आईबीसीए के पास व्यापक आधार और कई क्षेत्रों में कई गुना संबंध स्थापित करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण होगा और ज्ञान साझा करने, क्षमता निर्माण, नेटवर्किंग, वकालत, वित्त और संसाधन समर्थन, अनुसंधान और तकनीकी सहायता, शिक्षा और जागरूकता में मदद मिलेगी।
- सतत विकास और आजीविका सुरक्षा के लिए शुभंकर के रूप में बड़ी बिल्लियों के साथ, भारत और बड़ी बिल्ली श्रेणी के देश पर्यावरणीय लचीलेपन और जलवायु परिवर्तन शमन पर बड़े प्रयासों की शुरुआत कर सकते हैं, साथ ही एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं जहां प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र फलते-फूलते रहें, और आर्थिक और विकास में केंद्रीयता हासिल कर सकें। नीतियाँ.
- आईबीसीए स्वर्ण मानक बड़ी बिल्ली संरक्षण प्रथाओं के बढ़ते प्रसार के लिए एक सहयोगी मंच के माध्यम से तालमेल की परिकल्पना करता है, तकनीकी जानकारी और धन के कोष के केंद्रीय सामान्य भंडार तक

पहुंच प्रदान करता है, मौजूदा प्रजाति-विशिष्ट अंतर सरकारी प्लेटफार्मों, नेटवर्क और संरक्षण पर अंतरराष्ट्रीय पहल को मजबूत करता है। और सुरक्षा तथा हमारे पारिस्थितिक भविष्य को सुरक्षित करने और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में सहायता करता है।

- इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस समग्र और समावेशी संरक्षण परिणामों को प्राप्त करने के लिए सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ जैव विविधता नीतियों को एकीकृत करने के महत्व को पहचानता है।
- IBCA शासन में एक सभा शामिल है। गठबंधन प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करता है और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को कम करता है। बड़ी बिल्लियों और उनके आवासों की सुरक्षा करके, आईबीसीए प्राकृतिक जलवायु अनुकूलन, जल और खाद्य सुरक्षा और इन पारिस्थितिक तंत्रों पर निर्भर हजारों समुदायों की भलाई में योगदान देता है।
- आईबीसीए आपसी लाभ के लिए देशों के बीच सहयोग स्थापित करेगा और दीर्घकालिक संरक्षण एजेंडे को आगे बढ़ाने में अत्यधिक योगदान देगा। सदस्यों की संख्या, स्थायी समिति और एक सचिवालय जिसका मुख्यालय भारत में है। समझौते की रूपरेखा (क़ानून) बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) की तर्ज पर तैयार की गई है और इसे अंतर्राष्ट्रीय संचालन समिति (आईएससी) द्वारा अंतिम रूप दिया जाना है।
- आईबीसीए ने पांच वर्षों (2023-24 से 2027-28) के लिए भारत सरकार की 150 करोड़ रुपये की प्रारंभिक सहायता प्राप्त की है। कोष संवर्धन द्विपक्षीय और बहुपक्षीय एजेंसियों से योगदान से होगा तथा अन्य उपयुक्त संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और दाता एजेंसियों की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के उपाय किए जाएंगे।

विश्व वन्यजीव दिवस 2024

सुर्खियों में क्यों?

- 3 मार्च 2024 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड (WWF) द्वारा ओखला बर्ड सैंक्चुअरी में वर्ल्ड वाइल्डलाइफ डे, 2024 का आयोजन किया गया ।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। यह दिवस दुनिया भर में लुप्त हो रही वन्य जीव व वनस्पति की प्रजातियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है।
- वर्ष 2024 का थीम 'लोगों और ग्रह को जोड़ना: वन्यजीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज' है।
- यह थीम वन्यजीव संरक्षण प्रयासों में डिजिटल नवाचार द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालती है। यह वन्यजीवों के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने, उनकी आबादी की निगरानी करने और लुप्तप्राय प्रजातियों और उनके आवासों की रक्षा के लिए नवीन समाधान विकसित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के महत्व पर प्रकाश डालता है।
- इस दिवस का आयोजन वर्ष 2013 से किया जा रहा है। 20 दिसंबर 2013 को अपने 68वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में घोषित किया। यह दिन उस दिन के रूप में महत्वपूर्ण है जब 1973 में वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- वर्ष 1973 में वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) पर हस्ताक्षर किए गए जबकि जुलाई 1975 में लागू हुआ था। वर्तमान में CITES के 183 पक्षकार देश हैं और भारत भी इसका सदस्य है।

सेला सुरंग (Sela Tunnel)

सुर्खियों में क्यों?

- 09 मार्च, 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग परियोजना को वर्चुअल तरीके से राष्ट्र को समर्पित किया।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि इस सुरंग की आधारशिला 09 फरवरी, 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रखी थी और इसका निर्माण कार्य 01 अप्रैल, 2019 को शुरू हुआ था।
- सेला सुरंग दुनिया की सबसे लंबी द्वि-लेन सुरंग है, जिसका निर्माण

सीमा सड़क संगठन द्वारा 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर किया गया है, जिसकी लागत 825 करोड़ रुपये है।

- असम में तेजपुर को अरुणाचल प्रदेश में पश्चिम कामेंग जिले के तवांग से जोड़ने वाली यह सुरंग तवांग को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, सशस्त्र बलों की तैयारियों को मजबूती देगी और सीमा क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ाएगी।

ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2024

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2024 जारी किया है। IEA का ग्लोबल मीथेन ट्रैकर (GMT) ऊर्जा क्षेत्र में मीथेन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में एक अनिवार्य उपकरण है।

ग्लोबल मीथेन ट्रैकर (GMT) के बारे में

- नवीनतम IEA ग्लोबल मीथेन ट्रैकर ऊर्जा क्षेत्र से मीथेन उत्सर्जन पर सबसे हाल ही में उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित है और इसमें नए वैज्ञानिक अध्ययन, माप अभियान और उपग्रहों से एकत्र की गई जानकारी शामिल है।
- IEA के अनुमान के अनुसार वर्ष 2023 में लगभग 120 मिलियन टन उत्सर्जन जीवाश्म ईंधन से जुड़ा था, जिसमें लगभग 80 मिलियन टन उन देशों से आया था जो वैश्विक स्तर पर मीथेन के शीर्ष 10 उत्सर्जकों में से हैं।
- तेल और गैस परिचालन से संयुक्त राज्य अमेरिका मीथेन का सबसे बड़ा उत्सर्जक है, इसके बाद रूस और चीन का स्थान आता है।
- वर्ष 2023 में वैश्विक स्तर पर जीवाश्म ईंधन संचालन में मीथेन की हानि 170 बिलियन क्यूबिक मीटर थी, जो कतर के प्राकृतिक गैस उत्पादन से अधिक थी।
- नॉर्वे और नीदरलैंड में उत्सर्जन की तीव्रता सबसे कम है। मध्य पूर्व के देशों, जैसे सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में भी उत्सर्जन तीव्रता अपेक्षाकृत कम है, जबकि तुर्कमेनिस्तान और वेनेज़ुएला में सबसे अधिक है।
- 2023 में औसत ऊर्जा कीमतों के आधार पर, जीवाश्म ईंधन से होने वाले 120 मिलियन टन मीथेन उत्सर्जन में से लगभग 40% को बिना किसी शुद्ध लागत के टाला जा सकता है।
- पेरिस समझौते के अनुसार तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए दुनिया को 2030 तक जीवाश्म ईंधन से मीथेन उत्सर्जन में 75 प्रतिशत की कटौती करने की जरूरत है।

टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन (TWS)

सुर्खियों में क्यों?

- उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 मार्च 2024 को राज्य की सर्वाधिक सूखाग्रस्त तहसीलों में सूखे की स्थिति पर नजर रखने के लिए 100 टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन (TWS) स्थापित करने की योजना की घोषणा की, जिसमें बुंदेलखंड क्षेत्र के सात जिलों की सभी तहसीलें भी शामिल हैं।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- इस पहल का उद्देश्य TWS के माध्यम से राज्य के विभिन्न स्थानों के तापमान, सौर विकिरण, हवा की गति आदि को जानने के बाद उत्तर प्रदेश में लगातार सूखे की स्थिति से निपटना है।
- प्रारंभिक चरण में, TWS को सबसे अधिक सूखाग्रस्त 100 तहसीलों में स्थापित किया जाएगा। यह पहल सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और बुन्देलखंड के सात जिलों जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता देती है, जिन्हें हर साल सूखे का खतरा रहता है।
- सरकार ने इस परियोजना के लिए 10 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिससे सोनभद्र की सभी तहसीलों, मिर्ज़ापुर की दो तहसीलों और प्रत्येक जिले में एक तहसील में मौसम स्टेशनों की स्थापना सुनिश्चित की जा सके।
- TWS को रणनीतिक रूप से मौजूदा स्वचालित मौसम स्टेशनों (AWS) और स्वचालित वर्षा-गेज स्टेशनों (ARG) से 7-10 किलोमीटर की दूरी पर 10x10 मीटर की दूरी पर रखा जाएगा।
- टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन उपकरणों और सेंसरों का एक संग्रह है जो वायुमंडलीय और मृदा की स्थिति को मापता है। एक ऑन-साइट मौसम स्टेशन आपके बढ़ते क्षेत्र में माइक्रॉक्लाइमेट की निगरानी की अनुमति देता है।

ए.एस. राजीव सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त

सुर्खियों में क्यों?

- 11 मार्च 2024 को ए.एस. राजीव ने केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली।
- श्री ए.एस. राजीव ने अपने कैरियर में एक बैंकर की तरह कार्य किये हैं, उनके पास चार प्रमुख बैंकों अर्थात् सिंडिकेट बैंक, इंडियन बैंक, विजया बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 38 वर्षों से अधिक कामकाज का अनुभव है।

केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) के बारे में

- केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission) एक शीर्ष भारतीय सरकारी निकाय है, जिसे सरकारी भ्रष्टाचार को संबोधित करने के लिए स्थापित किया गया था।
- इस आयोग का गठन संथानम समिति की सिफारिश पर फरवरी 1964 में की गई, जबकि केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 के द्वारा इसे सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया।
- यह केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है एवं केन्द्रीय सरकारी संगठनों में विभिन्न प्राधिकारियों को उनके सतर्कता कार्यों की योजना बनाने, निष्पादन करने, समीक्षा करने तथा सुधार करने में सलाह देता है।

- इस बहु-सदस्यीय आयोग में एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (अध्यक्ष) और अधिकतम दो सतर्कता आयुक्त (सदस्य) शामिल होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसमें प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), गृह मंत्री (सदस्य) और लोकसभा में विपक्ष के नेता (सदस्य) शामिल होते हैं।
- केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष (इनमें जो पहले हो) का होता है। वर्तमान में इसका अध्यक्ष सुरेश एन. पटेल है।
- CVC किसी भी मंत्रालय/विभाग के अधीन नहीं है। यह एक स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है। यद्यपि CVC अपने कार्यकलाप में अपेक्षाकृत स्वतंत्र है, लेकिन उसके पास न तो संसाधन हैं और न ही भ्रष्टाचार की शिकायतों पर कार्रवाई करने की शक्ति है। यह सिर्फ भ्रष्टाचार या कार्यालय के दुरुपयोग से संबंधित शिकायतें सुनता है और इस दिशा में उपयुक्त कार्रवाई की सिफारिश करता है।
- केंद्रीय सतर्कता आयोग कोई अन्वेषण एजेंसी नहीं है। यह या तो CBI के माध्यम से या सरकारी कार्यालयों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों (Chief Vigilance Officers- CVO) के माध्यम से मामले की जाँच/अन्वेषण कराता है।

अभ्यास 'भारत शक्ति'

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज राजस्थान के पोखरण में तीनों सेनाओं के लाइव फायर और त्वरित कार्रवाई अभ्यास के रूप में स्वदेशी रक्षा क्षमताओं के एक समन्वित प्रदर्शन का अवलोकन किया।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- 'भारत शक्ति' में देश की शक्ति के प्रदर्शन के रूप में स्वदेशी हथियार प्रणालियों और प्लेटफार्मों की एक श्रृंखला प्रदर्शित की जाएगी, जो देश की आत्मानिर्भारत पहल पर आधारित है।
- अभ्यास में भाग लेने वाले प्रमुख उपकरण और हथियार प्रणालियों में टी-90 (आईएम) टैंक, धनुष और सारंग गन सिस्टम, आकाश हथियार प्रणाली, लॉजिस्टिक्स ड्रोन, रोबोटिक म्यूल, उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर (एएलएच) और मानव रहित विमानों की एक श्रृंखला शामिल है।
- भारतीय सेना ने उन्नत जमीनी युद्ध और हवाई निगरानी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। भारतीय नौसेना ने समुद्री ताकत और तकनीकी परिष्कार को उजागर करते हुए नौसेना एंटी-शिप मिसाइलों, स्वायत्त कार्गो ले जाने वाले विमानों और हवाई लक्ष्यों का प्रदर्शन किया।
- भारतीय वायु सेना ने हवाई संचालन में वायु श्रेष्ठता और बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू विमान तेजस, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर तैनात किए।
- घरेलू समाधानों के साथ समकालीन और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने और उन पर काबू पाने के लिए भारत की तत्परता के स्पष्ट संकेत में, भारत शक्ति वैश्विक मंच पर भारत की घरेलू रक्षा क्षमताओं के लचीलेपन, नवाचार और ताकत पर प्रकाश डालती है।

- यह कार्यक्रम भारतीय सशस्त्र बलों की ताकत और परिचालन कौशल और स्वदेशी रक्षा उद्योग की सरलता तथा प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करके, रक्षा में आत्मनिर्भरता की दिशा में देश की मजबूत प्रगति का उदाहरण देता है।

कोचरब आश्रम का उद्घाटन

सुर्ख़ियों में क्यों?

- 12 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के साबरमती में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया और उन्होंने गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान का शुभारम्भ भी किया।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि 12 मार्च 1930 को ही गाँधीजी ने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत की थी।
- यह 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था। इसे आज भी गुजरात विद्यापीठ ने एक स्मारक और पर्यटन स्थल के रूप में संरक्षित रखा है।
- इस दिशा में गांधी आश्रम स्मारक परियोजना वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए महात्मा गांधी की शिक्षाओं और दर्शन को पुनर्जीवित करने में मदद करेगी।
- इस मास्टर प्लान के तहत आश्रम के मौजूदा पांच एकड़ क्षेत्र को 55 एकड़ तक विस्तारित किया जाएगा। 36 मौजूदा इमारतों का जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिनमें गांधीजी के निवास स्थान 'हृदय कुंज' सहित 20 इमारतों का संरक्षण किया जाएगा, 13 का जीर्णोद्धार किया जाएगा और 3 का पुनरुद्धार किया जाएगा।
- इस मास्टरप्लान में गृह प्रशासन सुविधाओं के लिए नई इमारतें, ओरिएंटेशन सेंटर जैसी आगंतुक सुविधाएं, चरखा कताई, हस्तनिर्मित कागज, कपास बुनाई और चमड़े के काम तथा सार्वजनिक उपयोगिताओं पर संवादात्मक कार्यशालाएं शामिल हैं।
- इन इमारतों में गांधीजी के जीवन के पहलुओं के साथ-साथ आश्रम की विरासत को प्रदर्शित करने के लिए संवादात्मक प्रदर्शनियां और गतिविधियां होंगी और गांधीजी के विचारों को संरक्षित और प्रसारित करने के लिए एक पुस्तकालय और अभिलेखागार भवन का निर्माण भी किया जाना है।
- यह स्मारक भावी पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा के रूप में काम करेगा, गांधीवादी विचारों को बढ़ावा देगा और ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों की सूचित प्रक्रिया के माध्यम से गांधीवादी मूल्यों के सार को जीवंत करेगा।

पीएम-सूरज पोर्टल

सुर्ख़ियों में क्यों?

- 13 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वंचित वर्गों को ऋण सहायता के लिए पीएम सूरज पोर्टल को लॉन्च किया।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- पीएम सूरज पोर्टल एक राष्ट्रीय पोर्टल है, जो सामाजिक उत्थान और रोजगार पर आधारित और जनकल्याण के लिए है। इस पोर्टल के जरिए ऋण सहायता स्वीकृत की जाएगी। इससे पात्र लोगों को ऋण लेने में सुविधा मिलेगी।
- इस पोर्टल के जरिए लोग आसानी से लोन ले पाएंगे, जिसमें 15 लाख रुपये तक के बिजनेस लोन के लिए आवेदन किया जा सकेगा।
- इससे बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और इसी पोर्टल के जरिए आवेदन किया जा सकेगा।
- इस पोर्टल का उद्देश्य समाज के सबसे वंचित वर्गों का उत्थान और सशक्तिकरण करना है। योजना अंतर्गत ऋण मुहैया कराया जाएगा।
- पीएम सूरज पोर्टल के अंतर्गत पात्र लोगों को बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, सूक्ष्म वित्त संस्थान और अन्य संगठनों के जरिए ऋण दिया जाएगा।

लैंगिक असमानता सूचकांक 2022

सुर्ख़ियों में क्यों?

- यूएनडीपी ने 13 मार्च 2024 को मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 में लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 जारी किया।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 के अनुसार 193 देशों में से भारत 0.437 अंक के साथ 108वें स्थान पर है। इस सूचकांक में 2021 की तुलना में 14 रैंक का महत्वपूर्ण सुधार आया है।
- लैंगिक असमानता सूचकांक 2021 में भारत का स्कोर 0.490 था और तब वह 191 देशों में से 122वें स्थान पर था।
- लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत की रैंक लगातार बेहतर हुई है, जो पिछले 10 वर्षों में देश में लैंगिक समानता हासिल करने में प्रगतिशील सुधार का संकेत देती है। वर्ष 2014 में भारत की रैंक 127 थी जो अब 108 हो गई है।
- महिलाओं के लिए दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक विकास और नीतिगत पहल के माध्यम से सशक्त बनाने की दिशा में सरकार द्वारा उठाये गए कदमों के कारण रैंक में सुधार हुआ है।
- रिपोर्ट के अनुसार सरकार की पहल बालिका शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता विकास और कार्यस्थल को लैंगिक सुगम बनाने जैसे कदम ने महिलाओं के जीवनशैली को बेहतर किया है।

लैंगिक असमानता सूचकांक के बारे में

- लैंगिक असमानता सूचकांक (Global Inequality Index-

GII) यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है जो पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता का एक माप है। कम जीआईआई मान लैंगिक अंतराल के छोटे अंतर को इंगित करता है, जबकि उच्च मान बड़े अंतर को इंगित करता है।

- लैंगिक असमानता सूचकांक को मापने के लिए तीन आयामों का उपयोग किया जाता है - प्रजनन स्वास्थ्य, सशक्तिकरण एवं श्रम बाज़ार में भागीदारी।
- यह इन आयामों में पुरुष और महिला उपलब्धियों के बीच असमानता के परिणामस्वरूप संभावित मानव विकास में होने वाले नुकसान का आकलन करता है।
- सूचकांक 0 यह दर्शाता है कि सभी मापे गए आयामों में पुरुषों और महिलाओं के साथ समान व्यवहार किया जाता है, और 1 यह दर्शाता है कि सभी मापे गए आयामों में एक लिंग के साथ यथासंभव खराब व्यवहार किया जाता है।

अभ्यास टाइगर ट्राइंफ - 24

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच टाइगर ट्रायम्फ-24 नामक मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) अभ्यास शुरू की गई।
- इसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच तत्परता और सहयोग को बढ़ाना है। यह अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच चल रही साझेदारी का एक हिस्सा है।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- इसे दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच तेजी से और सुचारू समन्वय को सक्षम करने के लिए एचएडीआर संचालन के संचालन के लिए अंतर-संचालनीयता में सुधार और मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को परिष्कृत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- भारत की ओर से, अभ्यास में भारतीय नौसेना के जहाज, अभिन्न हेलीकॉप्टर और लैंडिंग क्राफ्ट, भारतीय नौसेना के विमान, भारतीय सेना के जवान और वाहन, भारतीय वायु सेना के विमान और हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। इसके अलावा, भारत की ओर से रैपिड एक्शन मेडिकल टीम (RAMT) भी भाग लेगी।
- इसके अलावा, अमेरिका का प्रतिनिधित्व अमेरिकी नौसेना के जहाजों द्वारा किया जाएगा जिसमें अमेरिकी मरीन कोर और अमेरिकी सेना के सैनिक शामिल होंगे।
- एचएडीआर में अलग-अलग चरण होंगे। पहला चरण हार्बर चरण है जो विशाखापत्तनम में 18 मार्च से 25 मार्च तक है। इस चरण में दोनों नौसेनाओं के कर्मियों के बीच प्रशिक्षण दौरे, विषय वस्तु विशेषज्ञ आदान-प्रदान, खेल कार्यक्रम और सामाजिक संपर्क शामिल हैं।
- दूसरा चरण समुद्री चरण होगा। इसकी शुरुआत 25 मार्च से होगी और समापन 31 मार्च को होगा. यह काकीनाडा में आयोजित किया जाएगा. इस चरण में भाग लेने वाले जहाज होंगे, जिनमें सवार सैनिक, अनुरूपित परिदृश्यों के आधार पर समुद्री, उभयचर और एचएडीआर संचालन करेंगे।
- इससे पहले, भारत और अमेरिका के बीच पहला टाइगर ट्रायम्फ-24 अभ्यास 2019 में नौ दिनों की अवधि के लिए हुआ था।

नई दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर

सुर्खियों में क्यों?

- स्विस संगठन IQAir द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार, बिहार का बेगुसराय दुनिया के सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र के रूप में उभरा, जबकि दिल्ली को सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाली राजधानी के रूप में पहचाना गया।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- 2023 में भारत में 54.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की औसत वार्षिक PM2.5 सांद्रता के साथ, बांग्लादेश (79.9 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर) और पाकिस्तान (73.7 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर) के बाद 134 देशों में से तीसरी सबसे खराब वायु गुणवत्ता थी।
- 2022 में, भारत को औसत PM2.5 सांद्रता 53.3 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के साथ आठवें सबसे प्रदूषित देश के रूप में स्थान दिया गया था।
- बेगूसराय 118.9 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की औसत PM2.5 सांद्रता के साथ विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र के रूप में सामने आया।
- दिल्ली का PM2.5 स्तर 2022 में 89.1 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से घटकर 2023 में 92.7 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गया। राष्ट्रीय राजधानी को 2018 से लगातार चार बार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा दिया गया।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि अनुमान है कि भारत में 1.36 अरब लोग पीएम2.5 सांद्रता का अनुभव करते हैं जो विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा अनुशंसित वार्षिक दिशानिर्देश स्तर 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक है।
- PM2.5 वायु प्रदूषण के संपर्क में आने से कई स्वास्थ्य स्थितियां पैदा होती हैं और बिगड़ जाती हैं, जिनमें अस्थमा, कैंसर, स्ट्रोक और फेफड़ों की बीमारी शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।
- सूक्ष्म कणों के ऊंचे स्तर के संपर्क में आने से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास ख़राब हो सकता है, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं और मधुमेह सहित मौजूदा बीमारियाँ जटिल हो सकती हैं।

सरस्वती सम्मान 2023

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में नई दिल्ली के प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनके पद्य उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान, 2023 से सम्मानित करने की घोषणा की गई।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- 1991 में स्थापित, सरस्वती सम्मान देश के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है।
- यह हर साल किसी भारतीय नागरिक द्वारा किसी भारतीय भाषा में लिखी गई और पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है।
- 1959 में केरल के तिरुवल्ला में जन्मे वर्मा ने मलयालम और अंग्रेजी दोनों में अनुकरणीय साहित्यिक कृतियों के साथ एक द्विभाषी लेखक के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।
- वह समकालीन मलयालम साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण आवाज़ों में से एक के रूप में उभरे हैं, उनके काम में परंपरा और आधुनिकता का संगम दिखता है।
- दशकों के करियर में, वर्मा ने 30 से अधिक किताबें लिखी हैं, जिनमें एक दर्जन कविता संग्रह, पद्य में तीन उपन्यास, समकालीन सामाजिक-राजनीतिक परिवेश और साहित्य पर आठ किताबें और आलोचना में निबंधों के सात संग्रह शामिल हैं।
- उन्होंने राष्ट्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित 70 से अधिक पुरस्कार जीते हैं।

ग्रिड-इंडिया को मिनीरत्न कंपनी का दर्जा

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड (GRID-INDIA) ने मिनीरत्न श्रेणी-I केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSE) का दर्जा प्राप्त करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई यह मान्यता, देश के विद्युत परिदृश्य में ग्रिड-इंडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है।
- 2009 में स्थापित, ग्रिड-इंडिया के पास भारतीय पावर सिस्टम के निर्बाध संचालन की देखरेख करने, विद्युत ऊर्जा के कुशल हस्तांतरण को सुनिश्चित करने, विश्वसनीयता, अर्थव्यवस्था पर ध्यान देने के साथ ट्रांस-नेशनल पावर एक्सचेंज की सुविधा प्रदान करने का महत्वपूर्ण दायित्व है।
- यह प्रतिस्पर्धी और कुशल थोक बिजली बाजारों की सुविधा प्रदान करता है और निपटान प्रणालियों का प्रबंधन करता है।
- पांच क्षेत्रीय लोड डिस्पैच सेंटर (आरएलडीसी) और नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर (एनएलडीसी) से युक्त, ग्रिड-इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे जटिल बिजली प्रणालियों में से एक, अखिल भारतीय सिंक्रोनस ग्रिड के प्रबंधन की विशाल जिम्मेदारी निभाती है।
- वर्षों से, ग्रिड-इंडिया के कार्य बिजली प्रणालियों के एकीकरण, बढ़ती ऊर्जा मांगों, नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) स्रोतों के प्रसार, आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति के साथ-साथ बदलते नियमों और बाजार की गतिशीलता के जवाब में गतिशील रूप से विकसित हुए हैं।
- एक ज्ञान-संचालित संगठन के रूप में, ग्रिड-इंडिया बिजली क्षेत्र की बदलती जरूरतों के अनुरूप भारत सरकार द्वारा सौंपे गए विविध कार्यों को पूरा करने के लिए समर्पित है।
- इसकी अटूट प्रतिबद्धता क्षेत्रीय और राष्ट्रीय बिजली प्रणालियों के एकीकृत संचालन को सुनिश्चित करने, अत्यधिक विश्वसनीयता, सुरक्षा और आर्थिक दक्षता के साथ विद्युत ऊर्जा हस्तांतरण की सुविधा सुनिश्चित करने में निहित है।

भारत टीबी रिपोर्ट 2024

सुर्खियों में क्यों?

- केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में भारत टीबी रिपोर्ट 2024 जारी की है।

रिपोर्ट से संबंधित प्रमुख बिंदु

- भारत में तपेदिक का शीघ्र पता लगाने और उपचार शुरू करने के प्रयासों के साथ-साथ कई सामुदायिक सहभागिता प्रयासों के परिणामस्वरूप टीबी की घटनाओं (हर साल सामने आने वाले नए मामले) में वर्ष 2015 तक 16% की गिरावट आई है और टीबी के कारण मृत्यु दर में 18% की कमी आई है।

TB CASES IN INDIA OVER THE YEARS

	India TB Report 2020	2023	2024
Estimated TB cases	26.9 lakh	27.4 lakh	27.8 lakh
Number of cases reported	24.04 lakh	24.2 lakh	25.5 lakh
Reporting from private sector	6.8 lakh	7.3 lakh	8.4 lakh
% cases from private sector	28.20%	30%	32.90%
Estimated mortality	4.36 lakh	3.2 lakh	3.2 lakh

- भारत में टीबी की घटना दर 2015 में 237 प्रति लाख जनसंख्या से गिरकर 2022 में 199 प्रति लाख जनसंख्या हो गई है, जबकि मृत्यु दर 2015 में 28 प्रति लाख जनसंख्या से घटकर 2022 में 23 प्रति लाख जनसंख्या हो गई है।
- ध्यातव्य रहे, भारत ने इस बीमारी को खत्म करने के लिए 2025 तक का लक्ष्य रखा है।
- रिपोर्ट में जारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले नौ वर्षों में वार्षिक आधार पर टीबी मामलों की समग्र अधिसूचना में 50% से अधिक का सुधार हुआ है, जबकि उत्तर प्रदेश में अधिसूचनाओं में सबसे अधिक उछाल देखा गया (पिछले वर्ष की तुलना में 21%)), उसके बाद बिहार (15%) का स्थान है।
- COVID-19 महामारी के बाद, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP) ने राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (NSP) 2017-25 द्वारा निर्देशित, टीबी उन्मूलन में तेजी लाने की दिशा में एक यात्रा शुरू की।
- एनटीईपी ने 2023 में लगभग 1.89 करोड़ थूक स्मीयर परीक्षण और 68.3 लाख न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन परीक्षण (एनएएटी) आयोजित करते हुए मुफ्त नैदानिक सेवाएं प्रदान करना जारी रखा।
- निक्षय पोषण योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) ने टीबी रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना जारी रखा, लगभग एक करोड़ लाभार्थियों को लगभग 2,781 करोड़ रुपये वितरित किए गए।

विश्व क्षय रोग दिवस-2024

सुर्ख़ियों में क्यों?

- प्रतिवर्ष 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्षय रोग के कारण होने वाले विनाशकारी सामाजिक और आर्थिक प्रभावों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- विश्व क्षय रोग दिवस 2024 की थीम है - 'हां ! हम टीबी ख़त्म कर सकते हैं !' (Yes! We can end TB)।
- इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस एंड लंग डिजीज (IUATLD) ने दिया था, जिसके बाद यह विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा चिह्नित किया गया।
- गौरतलब है कि डॉ. रॉबर्ट कोच ने 24 मार्च को तपेदिक पैदा करने वाले जीवाणु के खोज की पुष्टि की थी। इस खोज को चिह्नित करने के लिए हर साल 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस मनाया जाता है।
- संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार हर दिन लगभग 4,000 लोग TB के कारण जान गंवाते हैं। इसके अलावा 30,000 लोग इस बीमारी से बीमार होते हैं।

तपेदिक (टीबी) के बारे में

- टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस (Mycobacterium tuberculosis') नामक जीवाणु के कारण होता है।
- इसे यक्ष्मा, तपेदिक, क्षयरोग भी कहा जाता है।
- टीबी आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकता है। टीबी का संचरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हवा (छींक, थूक, खांसी) के माध्यम से होता है।
- बीसीजी (BCG) टीबी की रोकथाम के लिए उपलब्ध एकमात्र टीका है जिसका प्रयोग पहली बार 1921 में मनुष्यों में किया गया था। भारत में, इसे 1948 में पेश किया गया था और 1962 में राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम का एक हिस्सा बन गया।
- भारत ने तपेदिक उन्मूलन (2017-2025), निक्षय पारिस्थितिकी तंत्र, निक्षय पोषण योजना, टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना भी शुरू की है।
- ध्यातव्य है कि भारत का लक्ष्य 2025 तक टीबी के मामलों को खत्म करना है। ज्ञात हो कि वैश्विक स्तर पर वर्ष 2030 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

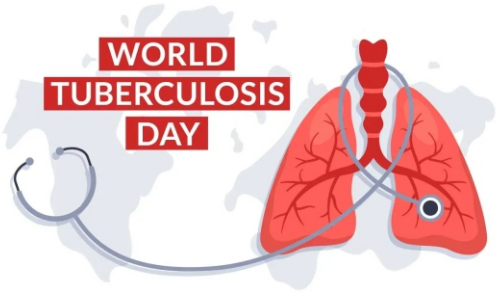

विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 जारी की गई है, जिसमें फिनलैंड लगातार सातवें साल सबसे खुशहाल देश है। यह रिपोर्ट 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है।
- इस रिपोर्ट में भारत सूचीबद्ध 143 देशों में से 126वें स्थान पर है।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- यह रिपोर्ट सामाजिक समर्थन, आय, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति जैसे कारकों पर विचार करते हुए 140 से अधिक देशों में खुशी के स्तर का मूल्यांकन करती है।
- विश्व खुशहाली रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है और इसमें छह कारकों को ध्यान में रखा जाता है - प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, किसी पर भरोसा करना, जीवन विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार से मुक्ति।
- फ़िनलैंड लगातार सातवें साल इस सूची में शीर्ष पर रहा, उसके बाद डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन रहे। इज़राइल ने भी रैंकिंग के शीर्ष पांच में जगह बनाई। इस बीच, कांगो, सिएरा लियोन, लेसोथो और लेबनान के बाद अफगानिस्तान को सबसे कम खुशहाल देश माना गया।
- हालांकि सूची में शीर्ष 10 देश कोविड-19 महामारी से पहले से ही वही बने हुए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी रैंकिंग में गिर गए हैं, जिससे कई पूर्वी यूरोपीय देशों के लिए सूची में ऊपर आने का रास्ता खुल गया है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका रैंकिंग में पिछले वर्ष 16वें स्थान से गिरकर इस वर्ष 23वें स्थान पर आ गया। इस वर्ष, कनाडा 15वें स्थान पर रहा जबकि ब्रिटेन 20वें, जर्मनी 24वें और फ्रांस 27वें स्थान पर रहा। मध्य पूर्वी देशों में संयुक्त अरब अमीरात 22वें और सऊदी अरब 28वें स्थान पर रहा। एशियाई देशों में सिंगापुर 30वें स्थान पर रहा। जापान 50 पर और दक्षिण कोरिया 51 पर।
- रिपोर्ट में पाया गया कि भारत में, अधिक उम्र उच्च जीवन संतुष्टि से जुड़ी है। हालाँकि, वृद्ध भारतीय महिलाओं ने वृद्ध पुरुषों की तुलना में कम जीवन संतुष्टि की सूचना दी।
- शिक्षा और जाति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, माध्यमिक या उच्च शिक्षा वाले वृद्ध वयस्कों और उच्च सामाजिक जातियों के लोगों ने औपचारिक शिक्षा के बिना अपने समकक्षों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की तुलना में उच्च जीवन संतुष्टि की सूचना दी।
- दुनिया भर में, हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम खुश थीं, जैसे-जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, लिंग अंतर बढ़ता गया।
- हालाँकि, जब वृद्ध लोगों (60 वर्ष और उससे अधिक आयु) में खुशी की

रैंकिंग की बात आई, तो डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और आइसलैंड - सभी नॉर्डिक राष्ट्र - सर्वोच्च स्थान पर रहे, जिसमें भारत 121वें स्थान पर रहा।

अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 का समापन

सुर्ख़ियों में क्यों?

- खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) ने 29 मार्च 2024 को FAO मुख्यालय, रोम, इटली में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष (आईवाईएम) 2023 का समापन समारोह आयोजित किया।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- उच्च-स्तरीय हाइब्रिड कार्यक्रम में प्रतिभागियों को व्यक्तिगत तौर पर और वर्चुअली दोनों तरह से शामिल होने की अनुमति दी गई और इसमें भारत सरकार की ओर से कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अपर सचिव श्रीमती मनिंदर कौर द्विवेदी सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों से सम्मानित गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए।
- गौरतलब है कि भारत के एक प्रस्ताव के बाद, जिसका 70 से अधिक देशों ने समर्थन किया, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2021 में अपने 75वें सत्र में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया था।
- अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित करने का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा और पोषण में पोषक अनाज/बाजरा/मोटे अनाज के योगदान के बारे में जागरूकता का प्रसार करना, पोषक अनाज के टिकाऊ उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार के लिये हितधारकों को प्रेरित करना तथा इन दोनों उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये अनुसंधान और विकास एवं विस्तार सेवाओं में निवेश बढ़ाने पर ध्यान देना है।

ईसीआई राष्ट्रीय पीडब्ल्यूडी आइकन (ECI National PwD Icon)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, प्रतिष्ठित पैरा-तीरंदाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता सुश्री शीतल देवी को भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा पीडब्ल्यूडी श्रेणी में राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया था।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- मतदाता शिक्षा और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए अपनी तरह की पहली पहल में, भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सहयोग से भारतीय बधिर क्रिकेट एसोसिएशन (आईडीसीए) टीम एवं दिल्ली और जिला क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) की टीम के बीच एक प्रदर्शनी क्रिकेट मैच का आयोजन किया।
- इस अवसर पर, प्रतिष्ठित पैरा-तीरंदाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता सुश्री शीतल देवी को पीडब्ल्यूडी श्रेणी में राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया।
- इस कार्यक्रम में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार और श्री सुखबीर सिंह संधू उपस्थित थे जिन्होंने विजेता टीम को सम्मानित किया।
- कार्यक्रम के दौरान, आयोग ने दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं के लिए एक समर्पित मतदाता मार्गदर्शिका भी लॉन्च की।
- व्यापक पुस्तिका में दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध आवश्यक प्रावधानों की रूपरेखा दी गई है, जिसमें मतदान केंद्रों पर ढांचागत, सूचनात्मक और प्रक्रियात्मक विवरण शामिल हैं, साथ ही डाक मतपत्रों के लिए प्रयोज्यता और प्रक्रिया भी शामिल है, जिससे एक सहज और सुखद मतदान अनुभव की सुविधा मिलती है।
- यह समावेशिता और सशक्तिकरण के प्रति ECI की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है और विकलांग मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में नामांकन करने और भाग लेने के लिए प्रेरित करेगा।

"सुभाष अभिनंदन" का उद्घाटन

सुर्ख़ियों में क्यों?

- 11 मार्च 2024 को भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के 134वें स्थापना दिवस के अवसर पर कानून एवं न्याय (स्वतंत्र प्रभार), संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित एक डिजिटल प्रदर्शनी "सुभाष अभिनंदन" का शुभारंभ किया।
- राष्ट्रीय अभिलेखागार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तिगत रिकॉर्ड को संरक्षित किया गया है | इस प्रदर्शनी में उनके जन्म से लेकर मौजूदा समय तक की अवधि को कवर करने वाले 16 खंड शामिल हैं।
- यह दस्तावेजों के माध्यम से उनके जीवन की एक झलक प्रदान करता है, जिसमें जानकी नाथ बोस की डायरी, उनके जन्म, उनके लोक सेवा परीक्षा परिणाम और अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया है। यह वर्ष 1920 से 1940 तक के संघर्ष के दशकों को अच्छी तरह से प्रलेखित किया गया है, जो उनके भाषणों, उनकी साहसिक यात्रा और आजाद हिंद फौज के संघर्ष की जानकारी प्रदान करता है।

सुभाष चंद्र बोस के बारे में

- नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का जन्म 23 जनवरी, 1897 को कटक में हुआ था। इनके जयंती के अवसर पर 'पराक्रम दिवस' मनाया जाता है |
- बोस पहली बार वर्ष 1938 में हरिपुरा में कॉन्ग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। वहीँ वर्ष 1939 में त्रिपुरी (Tripuri) में उन्होंने गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभि सीतारमैय्या (Pattabhi Sitaramayya) के खिलाफ फिर से अध्यक्ष पद का चुनाव जीता।
- उन्होंने एक नई पार्टी 'फॉरवर्ड ब्लॉक' की स्थापना की। इसका उद्देश्य अपने गृह राज्य बंगाल में राजनीतिक वामपंथ और प्रमुख समर्थन आधार को मज़बूत करना था।
- वह जुलाई 1943 में जर्मनी से जापान-नियंत्रित सिंगापुर पहुँचे वहाँ से उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा 'दिल्ली चलो' का नारा दिया |

करेंट अफेयर्स आधारित प्रश्न

1. **प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के औरंगाबाद में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी, जिसकी लागत है -**
   (a) 21,400 करोड़ रुपये
   (b) 21,600 करोड़ रुपये
   (c) 21,800 करोड़ रुपये
   (d) 21,200 करोड़ रुपये
2. **6 मार्च 2024 को INS जटायु को कहां कमीशन किया जाएगा ?**
   (a) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
   (b) लक्षद्वीप द्वीप समूह
   (c) खंभात की खाड़ी
   (d) कावारत्ती द्वीप
3. **विश्व वन्यजीव दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है ?**
   (a) इस वर्ष की थीम है- कनेक्टिंग पीपुल एंड प्लैनेट : एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन।
   (b) जंगली जानवरों और पौधों को मनाने के लिए हर साल 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस (WWD) मनाया जाता है।
   (c) विश्व वन्यजीव दिवस 2024 डिजिटल वन्यजीव संरक्षण में हमारे साझा स्थायी भविष्य के लिए आगे के अवसरों पर कला, प्रस्तुतियों और बातचीत के माध्यम से अंतर-पीढ़ीगत आदान-प्रदान और युवा सशक्तिकरण का एक मंच है।
   (d) इनमे से कोई भी नहीं
4. **डेफ-कनेक्ट 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा -**
   (a) पीएम नरेंद्र मोदी
   (b) राजनाथ सिंह
   (c) निर्मला सीतारमण
   (d) अमित शाह
5. **हाल ही में भारत ने विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल किस योजना के तहत तैनात किया है ?**
   (a) प्रोजेक्ट भीष्म
   (b) परियोजना राहत
   (c) प्रोजेक्ट वर्तक
   (d) प्रोजेक्ट जीवन
6. **राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - ऑयल पाम (NMEO-OP) हाल ही में खबरों में था, यह भारत सरकार द्वारा कब लॉन्च किया गया था ?**
   (a) अगस्त 2020
   (b) अगस्त 2021
   (c) अगस्त 2022
   (d) अगस्त 2023
7. **हाल ही में एक साथ चुनाव (एक राष्ट्र, एक चुनाव) पर उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी, इस समिति के अध्यक्ष हैं -**
   (a) एनके सिंह (b) डॉ. सुभाष सी. कश्यप
   (c) हरीश साल्वे (d) राम नाथ कोविन्द
8. **हाल ही में जारी "लैंगिक असमानता सूचकांक 2022" में भारत किस स्थान पर है ?**
   (a) 108 (b) 111
   (c) 115 (d) 118
9. **14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किन दोनों को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है ?**
   (a) राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार
   (b) ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू
   (c) सुखबीर सिंह संधू और राजीव कुमार
   (d) उत्पल कुमार सिंह और इंदीवर पांडे
10. **हाल ही में, भारत सरकार ने भारत में फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए 23 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं -**
    (a) विश्व बैंक (b) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
    (c) एशियाई विकास बैंक (d) न्यू डेवलपमेंट बैंक
11. **भारत के चुनाव आयोग द्वारा आम चुनाव 2024 घोषणा की गई है, आम चुनाव 2024 होंगे -**
    (a) 5 चरण में (b) 6 चरण में
    (c) 7 चरण में (d) 8 चरण में
12. **संयुक्त सैन्य अभ्यास "LAMITIYE-2024" कहाँ आयोजित किया जाएगा ?**
    (a) अंडमान और निकोबार (b) लक्षद्वीप
    (c) मालदीव (d) सेशेल्स
13. **इथेनॉल 100 ईंधन किसके द्वारा लॉन्च किया गया -**
    (a) पीएम नरेंद्र मोदी (b) हरदीप सिंह पुरी
    (c) नितिन गडकरी (d) धर्मेंद्र प्रधान
14. **हाल ही में फिनलैंड डायना (DIANA) में शामिल हुआ, जो एक पहल है -**
    (a) संयुक्त राष्ट्र (यूएन) का
    (b) सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन (सीएसटीओ) का
    (c) शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) का
    (d) उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) का

1. (a)	2. (b)	3. (d)	4. (b)	5. (a)	6. (b)	7. (d)	8. (a)
	9. (b)	10. (c)	11. (c)	12. (d)	13. (b)	14. (d)	

प्रयास
IAS ACADEMY
An Institute for UPSC & BPSC
PRAYAS PRELIMS TEST SERIES 2024
PRAYAS
70th BPSC PRELIMS
TEST SERIES 2024
• Exam Mode: Online & Offline
• Language: Hindi Medium & English Medium
STARTING FROM 04 MAY 2024

प्रयास
IAS ACADEMY
An Institute for UPSC & BPSC
GS
FOUNDATION
COURSE
FOR BPSC
English Medium
upto
50%
OFF*
MODE: Offline & Online
COMMENCING FROM
03rd MAY

प्रयास
IAS ACADEMY

An Institute For UPSC & BPSC

Pushpanjali Palace,
Boring Road Chauraha, Patna-800001

8818810183 | 8818810184

www.prayasiasacademy.com

prayasiasacademy101@gmail.com

prayasiasacademy